वर्ष 12 • अंक 306 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 11 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

सीसीआई के खिलाफ अदालत पहुंची एमेजॉन

पंकज मुंजाल पृष्ठ 2

हीरो साइकिल का रुख वैश्विक बाजार की ओर

डॉलर रु. 71.30 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 78.10 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40575 ▲ 72 रुपये | सेंसेक्स 40979.60 ▼ 162.20 | निफ्टी 12031.50 ▼ 66.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 12040.00 ▲ 08.50 | ब्रेंट क्रूड 53.70 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना आज

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान के बाद अब मंगलवार को होने जा रही मतगणना के सिलसिले में मतगणना केंद्रों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक्जिट पोलों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की जीत का अनुमान आने और चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत की घोषणा में देरी होने से विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर लोगों के बीच जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार मतगणना के लिए 33 पर्यवेक्षक होंगे।

एससी-एसटी कानून में संशोधन वैध: शीर्ष न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति संशोधन कानून, 2018 को संवैधनिक रूप से वैध करार देते हुए सोमवार को कहा कि अदालत उन मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां पहली नजर में मामला नहीं बनता हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में कहा कि इस कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने या वरिष्ठ अधिकारियों से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

महिंद्रा-फोर्ड संयुक्त उपक्रम को सीसीआई की मंजूरी

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने महिंद्रा ऐंड महिंद्रा द्वारा फोर्ड मोटर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर संयुक्त उपक्रम बनाने को मंजूरी दे दी। पिछले साल अक्टूबर में महिंद्रा ने अरडोर ऑटोमोटिव में 51 फीसदी हिस्सेदारी 657 करोड़ रुपये में खरीदी थी। शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी फोर्ड मोटर कंपनी और उसकी सहायक इकाइयों के पास है। सीसीआई ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और फोर्ड मोटर के संयुक्त उपक्रम को मंजूरी दे दी गई।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के पत्रकार को प्रतिष्ठित इम्का अवॉर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड के पत्रकार सोमेश झा को इफ्को-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अल्मनाई एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ बिज़नेस ऐंड इकनॉमिक रिपोर्टर अवॉर्ड, 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें 2019 में देश में बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में खोजी पत्रकारिता के लिए रविवार को भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली में अल्मनस ऑफ द इयर पुरस्कार भी दिया गया।

आज का सवाल

क्या मुआवजा प्रतिपूर्ति पर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ेगी तकरार

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या दूरसंचार क्षेत्र के कर्ज से बढ़ेगी बैंकों की मुश्किल?	हां	33.33%
	नहीं	66.67%

5 साल तक नुकसान की भरपाई का था वादा लेकिन केंद्र ने खड़े किए हाथ

राज्यों को उपकर से ही मुआवजा

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 10 फरवरी

राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी की भरपाई के लिए केंद्र के वादे के मुताबिक पूरा मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह रकम मुआवजा उपकर के जरिये एकत्र राशि में से दी जाएगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को जीएसटी या उपकर की दरें बढ़ाने पर सहमति जतानी चाहिए। इस बैठक की तारीख अभी तय नहीं की गई है।

इसके पहले माना जा रहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद 5 साल तक राज्यों को जो भी राजस्व का नुकसान होगा, उसकी पूरी तरह से भरपाई केंद्र सरकार करेगी। हाल में पेश किए गए आम बजट में पिछले वर्षों में एकत्र किए गए अतिरिक्त मुआवजा उपकर के विशेष वितरण का प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्यों को उनके नुकसान का पूरा मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं है। कई राज्यों में पहले के वर्षों की तुलना में जीएसटी राजस्व घटा है। वहीं उपकर भी जरूरत से कम आया है। इस तरह यह कमी करीब 30,000 करोड़ रुपये हो सकती है। बजट प्रस्ताव में विशेष

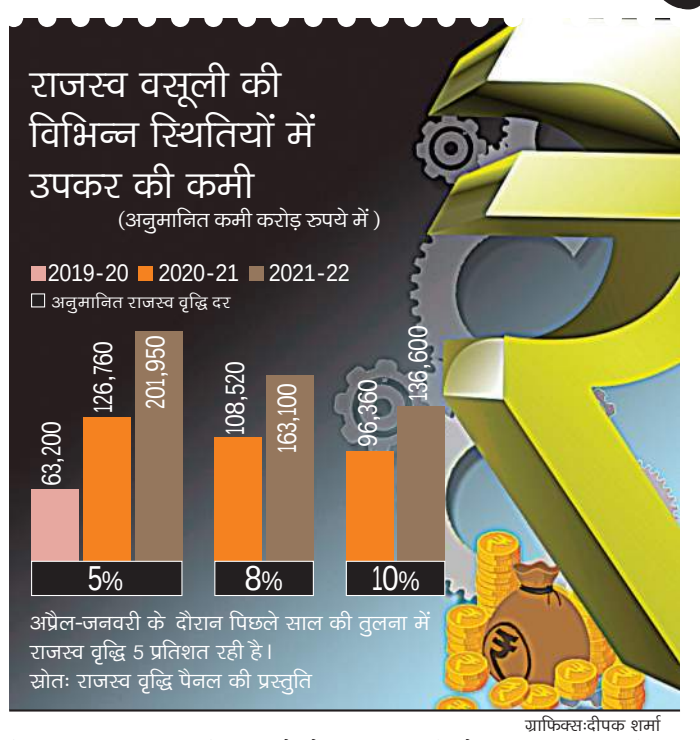

ग्राफिक्स:दीपक शर्मा

वितरण का प्रावधान किए जाने के बावजूद यह स्थिति है। अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष विशेष वितरण के लिए प्रावधान के बाद मुआवजे का हस्तांतरण सिर्फ मुआवजा उपकर से हुए संग्रह तक ही सीमित रहेगा। यह उपकर शीतल पेय पदार्थों, कोयला, पान मसाला, सिगरेट, वाहन पर 28 प्रतिशत कर के ऊपर लगाई गई राशि है।

बजट तैयार किए जाते समय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कार्यकारी चेयरमैन रहे बोर्ड के सदस्य जॉन जोसेफ ने कहा, 'कानून स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि मुआवजे के भुगतान के लिए मुआवजा उपकर लगाया जाएगा। इसी से मुआवजा दिया जाएगा। अगर इस कर से जरूरत भर को राशि नहीं आती है तो कानून में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप इसे केंद्रीय जीएसटी से ले सकते हैं। यह भी नहीं कहा गया है कि केंद्र सरकार इसे अपनी जेब से देगी।'

उन्होंने कहा कि पूरा मुआवजा पाने के लिए राज्य जीएसटी या उपकर दरें बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कानून में साफ है कि राज्यों को 14 प्रतिशत वृद्धि दर के हिसाब से पांच वर्षों तक राजस्व कमी की भरपाई की जाएगी। एक विशेषज्ञ ने कहा कि केंद्र को राज्यों को किए गए वादे से नहीं मुकरना चाहिए।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिसंबर में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि केंद्र से मुआवजा मिलने जा रहा है।

केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में उपकर में 63,200 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान जताया है। अप्रैल-जनवरी अवधि में जीएसटी संग्रह में 4.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सरकार पिछले दो वर्षों की 35,000 करोड़ रुपये की अधिशेष रकम दो किस्तों में मुआवजा कोष में हस्तांतरित करेगी। इसके बावजूद करीब 28,000 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है।

खुदरा ऋण पर बैंकों को 5 साल की राहत

अरूप रॉय
मुंबई, 10 फरवरी

- 31 जनवरी से 31 जुलाई के बीच दिए गए खुदरा ऋण पर सीआरआर बनाए रखने की जरूरत नहीं
- विश्लेषकों का कहना है कि जमा दरों में कटौती के बिना कोष की लागत कम करना है मकसद
- विकास के पटरी पर लौटने तक उपायों को बढ़ा सकता है बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि बैंकों को 31 जनवरी से 31 जुलाई के बीच एमएसएमई, आवास और वाहनों के लिए दिए गए ऋण के बराबर राशि के लिए अपनी जमा राशि पर पांच साल तक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल बैंक अपनी कुल जमा राशि की 4 फीसदी रकम सीआरआर के रूप में रखते हैं।

अलबत्ता, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में तीन उत्पादक क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण पर सीआरआर में कुछ रियायत देने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसलिए बैंकों से कहा गया है कि वे इन तीन क्षेत्रों को छह महीने के दौरान ऋण के रूप में दी गई राशि के बराबर रकम को अपने कुल जमा आधार से अलग कर सकते हैं और उन्हें इस राशि पर पांच साल तक सीआरआर बनाए रखने की जरूरत नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पांच साल की अवधि बैंकों के लिए पर्याप्त अवधि है। आवास ऋण लंबे समय तक चल सकता है जबकि वाहन ऋण की अवधि सात साल होती है। इस दौरान ऋण पोर्टफोलियो में कई बदलाव आएंगे क्योंकि सभी खुदरा ऋणों को अब रीपो से जोड़ दिया गया है और हर तिमाही उनमें बदलाव की जरूरत होगी। इससे ऋण पोर्टफोलियो की कम से कम एक श्रेणी में ग्राहकों को दरों में कटौती का लाभ मिलेगा। **(शेष पृष्ठ 4 पर)**

शाहीन बाग में सड़क अवरुद्ध कर असुविधा पैदा नहीं कर सकते: कोर्ट

भाषा
नई दिल्ली, 10 फरवरी

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोग सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के पीठ ने शाहीनबाग से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटस जारी किए। अदालत ने कहा, 'आप सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकते। यदि आप विरोध करना चाहते हैं, तो ऐसा एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।' पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई निर्देश नहीं देगी। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीनबाग में चल रहे विरोध में शामिल होने के बाद घर लौटे माता-पिता के शिशु की मृत्यु के मामले का सोमवार को संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने चार महीने के बच्चे की मृत्यु के मामले का स्वत: संज्ञान लिए जाने पर कुछ वकीलों द्वारा आपत्ति किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले बच्चों को उनके स्कूलों में पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताए जाने के बारे में दो महिला अधिवक्ताओं के बयान पर भी दु:ख व्यक्त किया।

उधर, बड़ी संख्या में छात्र और नागरिक संगठनों के लोग सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी का विरोध करते हुए मंडी हाउस पर एकत्र हुए और जंतर मंतर की ओर कूच शुरू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक कर्मी तैनात थे।

कोरोना से फोन बाजार को रोना

नेहा अलावधी, पीरजादा अबरार और अर्णव दत्ता
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 10 फरवरी

चीन में कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने से प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों और स्मार्टफोन विनिर्माताओं जैसे ऐपल, वनप्लस और श्याओमी आदि की बिक्री प्रभावित हो सकती है। चीन में नए साल की छुट्टियों को सरकार ने आगे बढ़ा दिया था और सोमवार से कारोबार शुरू होना था। हालांकि कुछ खबरों से पता चलता है कि चीन के कुछ प्रांतों में कंपनियों से 1 मार्च तक काम शुरू नहीं करने को कहा गया है। इंटरनैशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत में 15.23 करोड़ स्मार्टफोन का आयात किया गया और स्मार्टफोन की बिक्री के लिहाज से चीन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

2019 में भारत आने वाले कुल स्मार्टफोन में से 41.7 फीसदी की बिक्री ऑनलाइन हुई थी, जो 2018 की तुलना में 18.4 फीसदी अधिक है, वहीं ऑफलाइन बिक्री इस दौरान महज 1.6 फीसदी बढ़ी। ई-कॉमर्स उद्योग के अधिकारियों का कहना है चीन में विनिर्माण नहीं होने से उद्योग को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ई-कॉमर्स के एक कार्याधिकारी ने कहा, 'दोहरी समस्या हो रही है। एक तो चीन से बना बनाया उत्पाद नहीं आ रहा है और दूसरा

- भारत ने 2019 में पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी ज्यादा 15.25 करोड़ स्मार्टफोन का आयात किया
- इस साल भी स्मार्टफोन आयात की वृद्धि इसी के अनुरूप रहने की उम्मीद
- स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री : 41.7 फीसदी
- औसत बिक्री मूल्य : 163 डॉलर
- प्रमुख स्मार्टफोन कंपनी : श्याओमी, वीवो, सैमसंग, ओप्पो, रीयलमी

स्रोत : आईडीसी

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों जैसे फोन आदि के बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है।'

विश्लेषकों और उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश वेंडरों ने चीन में नए साल की छुट्टियों को देखते हुए पहले ही माल मंगवाकर स्टॉक कर लिया था, ऐसे में उन पर तत्काल असर पड़ने की आशंका नहीं है। आईडीसी इंडिया में सहायक शोध प्रबंधक, क्लाइंट डिवाइसेस उपासना जोशी ने कहा, 'मौजूदा हालात में पहली तिमाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन नए मॉडल पर असर पड़ सकता है।' उन्होंने कहा कि कारखानों में काम नहीं हो रहा है और ऐसी ही स्थिति एक और महीने रही तो फोनों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

हालांकि फिलहाल मोबाइल फोन के दाम में इजाफा होने की संभावना नहीं है। आईडीसी के अनुमान के मुताबिक पिछले साल स्मार्टफोन की बिक्री 8 फीसदी बढ़ी थी और इस बार भी इसकी वृद्धि इतनी ही रहने की उम्मीद है। ऐसे में स्मार्टफोन के दाम बढ़ाने से मांग पर असर पड़ने की आशंका है।

लेकिन अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी चिप्स, कंप्रेसर, टेलीविजन पैनल्स आदि की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और गोदरेज अप्लाइंसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने कहा, 'उत्पादन निलंबित करने की अवधि बढ़ाए जाने के बारे में चीनी वेंडरों से कोई संदेश नहीं मिला है। लेकिन इसे फरवरी अंत तक बढ़ाया जाता है तो भारत में मार्च में उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं और अप्रैल में आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।'

खबरों में रहे स्टॉक

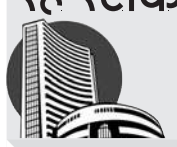

एवेन्यू सुपरमार्ट्स

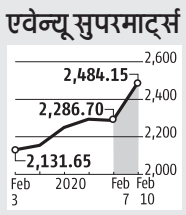

बाजार पूंजीकरण 1.56 लाख करोड़ रुपये की नई ऊंचाई पर

₹ 2,286.70 पिछला बंद भाव
₹ 2,484.15 आज का बंद भाव
▲ 8.64 %

टाटा स्टील

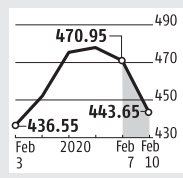

तीसरी तिमाही में 1,085 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा

₹ 470.95 पिछला बंद भाव
₹ 443.65 आज का बंद भाव
▼ 5.80 %

मदरसन सुमी सिस्टम्स

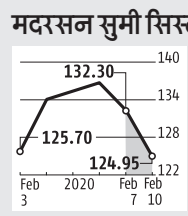

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 44 फीसदी घटा

₹ 132.30 पिछला बंद भाव
₹ 124.95 आज का बंद भाव
▼ 5.56 %

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा

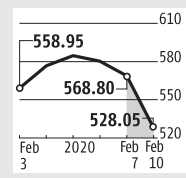

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 55 फीसदी घटा

₹ 568.80 पिछला बंद भाव
₹ 528.05 आज का बंद भाव
▼ 7.16 %

एमआरएफ

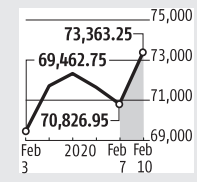

तीसरी तिमाही में एबिटा मार्जिन बढ़कर 15.3 फीसदी हुआ

₹ 70,826.95 पिछला बंद भाव
₹ 73,363.25 आज का बंद भाव
▲ 3.58 %

संक्षेप में

गेल का मुनाफा 25 फीसदी घटा

गेल इंडिया का दिसंबर, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 25 फीसदी से अधिक घट गया। शुद्ध लाभ 25.6 फीसदी घटकर 1,250.65 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,681.23 करोड़ रुपये रह था। कंपनी का मुनाफा घटकर 2.77 रुपये प्रति शेयर रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3.73 रुपये प्रति शेयर रहा था। *भाषा*

भारत फोर्ज का तिमाही लाभ 81 फीसदी घटा

वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 81.37 फीसदी की गिरावट के साथ 40.44 करोड़ रुपये पर आ गया। वित्त वर्ष 2018-19 की अक्टूबर-दिसंबर अवधि में यह आंकड़ा 216.96 करोड़ रुपये रहा था। *भाषा*

कार बिक्री की सुस्त पड़ी रफ्तार

जनवरी में कार बिक्री 6 फीसदी घटी, कोरोना के कारण आगे सुधार में होगी देरी

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 10 फरवरी

बिक्री को रफ्तार देने के लिए तमाम छूट की पेशकश के बावजूद वाहन कंपनियां घरेलू वाहन बाजार में पिछले एक दशक की सबसे खराब स्थिति से उबर नहीं पाई है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 6.2 फीसदी घटकर 2,62,714 वाहन रह गई। पिछले साल जनवरी में 2,80,091 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी।

जनवरी में वाहनों की बिक्री कमजोर रहने का असर शेयर बाजार पर भी दिखा जहां वाहन कंपनियों के शेयर में आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। जनवरी में कमजोर बिक्री और कोरोनावायरस के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका में निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल इस वायरस के चपेट में चीन है लेकिन उसका प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखल पर दिख रहा है।

एमजी मोटर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा, 'फरवरी के लिए डिलिवरी में निश्चित तौर पर देरी होगी।' हालांकि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि मौजूदा वाहन मेले में प्रदर्शित नए मॉडलों और प्रौद्योगिकी से वाहन उद्योग की तस्वीर बदल जाएगी।

दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की शोरूम बिक्री में भी दो अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि मौजूदा आर्थिक मंदी अभी खत्म नहीं होने वाली है। जनवरी की बिक्री में कमजोर वृद्धि पिछले साल दिसंबर की ही तरह है। पिछले साल दिसंबर में दो महीनों यानी अक्टूबर और नवंबर के मामूली सुधार के बाद बिक्री में गिरावट आई थी। उस दौरान त्योहारी छूट के कारण बिक्री में सुधार दिखा था। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक व सीईओ गुएंटर बट्सचेक ने हाल में बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा था, मेरे मुताबिक मंदी अभी जारी है और अक्टूबर व नवंबर में तेजी त्योहारी खरीद के कारण देखने को मिली थी।

दिसंबर में भी बीएस-4 वाहनों में काफी छूट मिली थी क्योंकि कंपनियां बीएस-6 के नियम की ओर बढ़ने से पहले यथासंभव अपनी इन्वेंट्री निकालने की कोशिश कर रही थीं।

साथ ही, ज्यादातर विनिर्माताओं ने माह के दौरान बिक्री में गिरावट दर्ज की क्योंकि माह के दौरान उत्पादन घटाया गया ताकि बीएस-4 उत्सर्जन नियमों से लैस वाहनों की इन्वेंट्री नियंत्रित रहे।

जनवरी में कारों की बिक्री

श्रेणी	जनवरी 2020	जनवरी 2019	% बदलाव
यात्री कार	262,714	280,091	-6.20
वाणिज्यिक वाहन	75,289	87,591	-14.04
तिपहिया वाहन	60,903	54,043	12.69
दोपहिया वाहन	13,41,005	15,97,528	-16.06
कुल	17,39,975	20,19,253	-13.83

स्रोतः सायम

हीरो साइकिल का रुख वैश्विक बाजार की ओर

शैली सेठ मोहिले
ग्रेटर नोएडा/मुंबई, 10 फरवरी

करीब दो वर्ष पहले हीरो साइकिल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पंकज एम मुंजाल लुधियाना में अपने आवास पर आईफोन पर उंगली घुमा रहे थे। अचानक उनकी नजर ई-साइकिल की एक तस्वीर पर पड़ी जिसे स्पेन में लॉन्च किया गया था।

तत्काल बाद उन्होंने अपने मुख्य कार्याधिकारी और अनुसंधान एवं विकास प्रमुख से इस संबंध में फोन पर बातचीत की। बाद में एक दिन बैठक कर उन्होंने हीरो में उसी तरह की साइकिल बनाने पर चर्चा की। इस प्रकार हीरो का रुख ई-साइकिल की ओर हो गया।

मुंजाल ने कहा कि उनके दिमाग में यह विचार 'असफलता के डर' से आया। कंपनी का प्रमुख कारोबार- मैनुअल पैडल वाली साइकिल- सिकुड़ रहा था। उन्होंने ऑटो एक्सपो में बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'आप वृहत बाजार की प्रवृत्तियों को बदल नहीं सकते बल्कि आपको खुद उसके अनुरूप ढालना होगा।' ऑटो एक्सपो में उनकी कंपनी ने विभिन्न मॉडलों की झलक दिखाई है जो कंपनी के भविष्य को आकार देंगे। इनमें स्ट्रैपहैंगर, इसेंशिया कनेक्ट और ईजी स्टेप श्रृंखला के ईलेक्ट्रिक साकिल शामिल हैं। ईजी स्टेप को मोड़ने लायक बॉडी और 7 स्पीड गियर के साथ उतारा गया है।

भारत में साइकिल की बिक्री रफ्तार घटी है और 2019-20 में करीब 10 फीसदी की गिरावट आने की आशंका है। हालांकि हीरो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 40 फीसदी हो गई जो एक साल पहले 36 फीसदी थी।

ई-साइकिल के सबसे बड़े बाजार यूरोप में मौजूद अवसरों को भांपते हुए हीरो ने 2018 में लैक्ट्रो ब्रांड को लॉन्च करते हुए ई-साइकिल कारोबार में कदम रखा था। इसी साल जनवरी में कंपनी ने जर्मनी की ई-साइकिल विनिर्माता एचएनएफ ग्रुप में रणनीतिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हीरो गठजोड़ के लिए हॉलेंड की एक कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। इस महीने के आखिर तक इस सौदे की घोषणा हो जाएगी।

आईओबी का कर पूर्व घाटा बढ़ा

बीएस संवाददाता
चेन्नई, 10 फरवरी

इंडियन ओवरसीज बैंक का कर पूर्व नुकसान दिसंबर तिमाही में बढ़कर 5,901.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 609.14 करोड़ रुपये रहा था। बैंक ने कहा कि एनपीए के लिए उच्च प्रावधान (5,564 करोड़ रुपये) के कारण घाटे में बढ़ोतरी हुई। बैंक की कुल आय इस अवधि में 8.6 फीसदी घटकर 5,197.94 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 5,688.59 करोड़ रुपये रही थी। 31 दिसंबर 2019 को कुल कारोबार 3,59,933 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,70,901 करोड़ रुपये रहा था।

दिसंबर तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 23,733.86 करोड़ रुपये (17.12 फीसदी) रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 35,787 करोड़ रुपये (23.76 फीसदी) रहा था। शुद्ध एनपीए घटकर 7,087.09 करोड़ रुपये (5.81 फीसदी) रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 17,987.92 करोड़ रुपये (13.56 फीसदी) रहा था। बैंक अपना शुद्ध एनपीए घटाकर 6 फीसदी से नीचे लाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जो त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर निकलने के मानकों में से एक है। बैंक रिकवरी, कम लागत वाली जमाओं और अग्रिम में कम पूंजी लगाने पर ध्यान देकर पीसीए से बाहर निकलने की योजना बना रहा है।

केंद्र सरकार ने दिसंबर तिमाही में बैंक में 4,360 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई और इसके बाद बैंक का सीआरएआर 10.43 फीसदी पर पहुंचा। प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 86.20 फीसदी रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 64.23 फीसदी रहा था।

कंपनी परिणाम

यूनियन बैंक का कर पूर्व लाभ बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में तीन गुने से ज्यादा बढ़कर 582.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। शुद्ध ब्याज आय में खासी बढ़ोतरी और फंसे कर्ज के लिए प्रावधान में कमी से लाभ में उछाल आई। पिछले साल की समान अवधि में बैंक का कर पूर्व लाभ 133.25 करोड़ रुपये रहा था।

बैंक का शुद्ध लाभ इस तिमाही में 574.58 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 153.21 करोड़ रुपये रहा था।

म्युचुअल फंडों में इक्विटी निवेश बढ़ा

मिडकैप व स्मॉलकैप फंडों में निवेश दोगुना, नई ऊंचाई पर परिसंपत्तियां

जश कृपलानी
मुंबई, 10 फरवरी

व्यापक बाजारों में तेजी से म्युचुअल फंड निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति में सुधार दर्ज हुआ है और उद्योग ने माह दर माह के आधार पर इक्विटी निवेश में 75 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। साथ ही मिडकैप व स्मॉलकैप योजनाओं में जनवरी के इक्विटी निवेश का करीब एक तिहाई निवेशित हुआ।

स्मॉल व मिडकैप फंडों में निवेश माह दर माह के आधार पर क्रमश: 154 फीसदी और 126 फीसदी सुधरा। स्मॉलकैप फंडों में जनवरी में 1,072 करोड़ रुपये का निवेश आया, वहीं मिडकैप में 1,798 करोड़ रुपये। कुल मिलाकर इक्विटी निवेश 7,877 करोड़ रुपये रहा। व्यापक बाजार में सुधार को लेकर फंड मैनेजरों का नजरिया तेजी का है, लेकिन आर्थिक सुधार पर नजर रखी जाएगी।

टाटा एमएफ के मुख्य निवेश अधिकारी राहुल सिंह ने कहा, मूल्यांकन के लिहाज से मिडकैप व स्मॉलकैप, लार्जकैप के मुकाबले भारी छूट पर कारोबार कर रहे हैं। हाल के महीनों में छूट में कुछ कमी आई है। हालांकि जब तक आर्थिक सुधार नहीं होता, यह तेजी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जनवरी के आखिर में म्युचुअल फंड उद्योग की परिसंपत्ति का आकार 27.85 लाख करोड़ रुपये रहा, जो नई ऊंचाई है। इस बीच, एसआईपी के जरिए निवेश मामूली सुधरकर 8,531 करोड़ रुपये रहा, जो नई ऊंचाई है। मिडकैप व स्मॉलकैप ने हाल के महीनों में लार्जकैप के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले तीन महीने में मिडकैप व स्मॉलकैप ने औसतन 9.5 फीसदी रिटर्न दिया है, वहीं लार्जकैप योजनाओं का रिटर्न एक फीसदी के आसपास रहा है। इस अवधि में सेंसेक्स व निफ्टी का रिटर्न क्रमश: 1.6 फीसदी व 1 फीसदी रहा है, जो बीएसई मिडकैप इंडेक्स और बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स से पीछे है, जिनमें क्रमश: 7.1 फीसदी और 9.7 फीसदी का रिटर्न मिला है।

निवेश में बड़ी उछाल

- माह दर माह के आधार पर इक्विटी निवेश में **75** फीसदी की बढ़ोतरी
- जनवरी के आखिर में इक्विटी परिसंपत्तियां **7.89** लाख करोड़ रुपये रहीं
- ऋण योजनाओं की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां **12.41** लाख करोड़ रुपये थी

जनवरी में सकल इक्विटी निवेश 9.4 फीसदी सुधरा, वहीं कुल निवेश निकासी में इसी दर से कमी आई।। उद्योग के प्रतिभागियों के मुताबिक, मिडकैप व स्मॉलकैप योजनाओं की ओर झुकाव बना रह सकता है। एडलवाइस एएमसी की मुख्य कार्याधिकारी राधिका गुप्ता ने कहा, अगर व्यापक बाजार में तेजी बनी रहती है तो हम मिडकैप व स्मॉलकैप योजनाओं में निवेश देख सकते हैं। निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी संदीप सिक्का ने कहा, पिछले कुछ महीनों से स्मॉलकैप फंडों की ओर रुझान नहीं था, लेकिन बाजार की हालिया तेजी ने स्मॉलकैप व मिडकैप फंडों में निवेश में इजाफा किया है। इसके परिणामस्वरूप स्मॉलकैप की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों में पिछले नौ महीने में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है।

डेट की बात करें तो निवेशकों का निवेश 1.09 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान लिक्विड व ओवरनाइट योजनाओं ने किया। लिक्विड योजनाओं में निवेशकों ने 59,682 करोड़ रुपये लगाए, वहीं ओवरनाइट योजनाओं में 22,652 करोड़ रुपये।

डेट श्रेणी में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन योजनाओं में 8,152 करोड़ रुपये का निवेश आया जबकि लो ड्यूरेशन में 5,562 करोड़ रुपये, मनी मार्केट फंड में 6,989 करोड़ रुपये और बैंकिंग व पीएसयू फंड में 3,032 करोड़ रुपये का निवेश आया। विशेषज्ञों ने कहा कि कि बैंक जमाओं की दर स्थिर बनी हुई है, ऐसे में निवेशक उच्च रिटर्न की तलाश में संभवत: ड्यूरेशन योजनाओं में निवश कर सकते हैं। जनवरी में इक्विटी परिसंपत्तियां 7.89 लाख करोड़ रुपये रही।

नए सीईओ के लिए विप्रो की नजर बाहरी उम्मीदवारों पर

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 10 फरवरी

विप्रो के मुख्य कार्याधिकारी आबिदअली नीमचवाला के इस्तीफे के बाद आईटी सेवा कंपनी शायद कुछ बाहरी उम्मीदवारों और कम से कम दो आंतरिक उम्मीदवारों पर नजर डाल रही है। सूत्रों के मुताबिक, सीईओ के पद के लिए जिन बाहरी नामों पर विचार हो रहा है उनमें एक्सेंचर के भास्कर घोष, टेक महिंद्रा के रितेश इदनानी, इन्फोसिस के रवि कुमार और एमफैसिस के नितिन राकेश शामिल हैं।

भास्कर घोष एक्सचेंचर टेक्नोलॉजी सर्विसेज के मुख्य कार्याधिकारी (समूह) हैं और उन्हें हाल में कंपनी की नई सीईओ जूली स्वीट के सलाहकार के तौर पर नामित किया गया है, जो मार्च से प्रभावी होगा और यह कदम संगठन के पुनर्गठन का हिस्सा है। रितेश इदनानी इन्फोसिस के पूर्व अधिकारी हैं और अभी टेक महिंद्रा के अध्यक्ष हैं, जो कंपनी के बीपीओ कारोबार का प्रबंधन करते हैं। रवि कुमार इन्फोसिस के डिप्टी सीओओ व अध्यक्ष हैं और नितिन राकेश एम्फैसिस के सीईओ हैं। इन्हें सीईओ के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है।

एचएफएस रिसर्च के संस्थापक व सीईओ पी फेर्स्ट ने कहा, विप्रो को एक ऐसे नेता की दरकार है जो चीजों में तेजी से बदलाव कर सके। अगर अगला सीईओ बोर्ड में महज येस मैन के तौर पर होगा तो वह कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। उन्होंने कहा, आंतरिक तौर पर संभावित उम्मीदवार राजन कोहली और मिलन राव हो सकते हैं।

राजन कोहली अभी विप्रो के डिजिटल व कंसल्टिंग डिविजन की अगुआई कर रहे हैं और मिलन राव जीई हेल्थकेयर से आए हैं और विप्रो के कोर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस मार्केटिंग, इनोवेशन व टेक्नोलॉजी की अगुआई कर रहे हैं। इस बारे में विप्रो के प्रवक्ता ने कहा, कंपनी सिर्फ बाहरी उम्मीदवारों पर नजर डाल रही है। विप्रो बोर्ड की गवर्नेंस, नॉमिनेशन व कंपनसेशन कमेटी की तरफ से खोज प्रक्रिया के तहत सीईओ के लिए सिर्फ बाहरी उम्मीदवारों पर नजर डाली जा रही है। इस पर हमारे पास टिप्पणी के लिए अभी कुछ और नहीं है।

तलाश जारी

- टेक महिंद्रा के रितेश इदनानी, एक्सेंचर के भास्कर घोष और इन्फोसिस के रवि कुमार को संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है
- सूत्रों ने कहा कि आंतरिक उम्मीदवारों मिलन राव, राजन कोहली का भी हो रहा आकलन
- विप्रो ने हालांकि कहा कि वह आबिदअली नीमचवाला के उत्तराधिकारी के लिए सिर्फ बाहरी उम्मीदवारों पर नजर डाल रही है

संक्षेप में

बीओबी ने 5-10 आधार अंक घटाई उधारी दरें

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए सीमांत लागत पर आधारित उधारी दरों (एमसीएलआर) में 10 आधार अंकों तक की कटौती की है, जो 12 फरवरी 2020 से लागू होगी। एक साल का एमसीएलआर 8.15 फीसदी होगा, जो पहले 8.25 फीसदी था। *बीएस*

इसूजू मोटर्स ने शुरू किया नया संयंत्र

जापान की यूटिलिटी वाहन विनिर्माता इसूजू मोटर्स इंडिया ने श्रीसिटी में दूसरे चरण का परिचालन शुरू कर दिया है। कंपनी ने यहां नई प्रेस शॉप फैसिलिटी और इंजन असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना 400 करोड़ रुपये के निवेश से हुई है। प्रेस शॉप और इंजन असेंबली से कंपनी का परिचालन और मजबूत होगा। पहले चरण में इसूजू ने श्रीसिटी में विनिर्माण शुरू किया था और विश्व प्रसिद्ध डी-मैक्स प्लेटफॉर्म पर पिक-अप्स व एसयूवी पेश किया। *बीएस*

कलपुर्जा निर्माताओं ने एक्सपो में उतारे नए सामान

कलपुर्जा निर्माताओं के लिए ऑटो एक्सपो 2020 में 400 कंपनियों ने 1,200 नए उत्पाद पेश किए। मारुति सुजूकी, टाटा मोटर्स, किया मोटर्स और अशोक लीलैंड समेत अग्रणी वाहन निर्माताओं ने अपने उत्पाद पेश किए। एक्मा के मुताबिक, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने इस शो में हिस्सा लिया। *बीएस*

देवयानी इंटरनैशनल करेगी 1,000 करोड़ रुपये निवेश

केएफसी, पिज्जा हट, टाको बेल, कोस्टा कॉफी जैसे वैश्विक रेस्तरां ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी देवयानी इंटरनैशनल लिमिटेड (डीआईएल) अगले पांच साल में इन ब्रांड के विस्तार पर करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने बताया कि डीआईएल की योजना अगले चार-पांच साल में केएफसी और पिज्जा हट की संख्या दोगुनी करने की है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि यम रेस्टोरेंट्स इंडिया उसकी एक निश्चित हिस्सेदारी खरीदेगी। डीआईएल यम की भारत में फ्रेंचाइजी सहयोगी है। *भाषा*

ब्रांडेड आटा बाजार में हिस्सा दोगुना करने का अदाणी विल्मर का इरादा

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 10 फरवरी

पैकेटबंद गेहूं के आटे के ब्रांड फॉर्च्युन आटा का कारोबार जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान 230 करोड़ रुपये के पार निकल गया, लेकिन खाद्य तेल निर्माता अदाणी विल्मर इस क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

आईएमआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए अदाणी विल्मर लिमिटेड के विपणन प्रमुख अजय मोटवानी ने सोमवार को कहा कि पैकेटबंद गेहूं के आटे के बाजार में इस ब्रांड की हिस्सेदारी अभी 0.6 फीसदी है। कंपनी दिसंबर 2020 तक संयंत्रों में उत्पादन की क्षमता का 80 फीसदी इस्तेमाल करेगी, ऐसे में कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

मोटवानी ने कहा, 3.5 लाख टन मासिक पैकेटबंद आटा बाजार में गेहूं का आटा यानी चक्की आटे की हिस्सेदारी 90 फीसदी है जबकि बाकी योगदान मल्टी ग्रेन आटा व रिफाइंड आटा आदि करती है। मोटवानी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी के पहले साल हमारे फॉर्च्युन ब्रांड आटे का कारोबार 230 करोड़ रुपये का हुआ। अब हम माह दर माह 10 फीसदी की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इस कैलेंडर वर्ष के आखिर तक अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का 80 फीसदी इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें साल 2020 के आखिर तक बाजार हिस्सेदारी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

नीमराणा में खुद के संयंत्र के अलावा अदाणी विल्मर अन्य चार संयंत्रों से गेहूं का आटा हासिल करती है, जिसकी संयुक्त क्षमता 29,500 टन मासिक है। हालांकि सालाना बिक्री 75,000 टन मासिक रहने के कारण कंपनी अभी अपनी क्षमता का महज 20 फीसदी इस्तेमाल कर पा रही है। कंपनी को हालांकि गैर-ब्रांडेड बाजार में स्थानीय आटा मिलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की टीम ने अपने फॉर्च्युन ब्रांड के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद सुनिश्चित की है।

मोटवानी ने कहा, गेहूं का प्रसंस्करण और पैकेजिंग हमारे अत्याधुनिक संयंत्रों में साफ-सुथरी व्यवस्था के तहत होता है। साथ ही कीड़ों से बचाने के लिए भी एक प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

हाल में रेडी टु कुक उत्पाद मसलन फॉर्च्युन खिचड़ी की पेशकश के बाद अदाणी विल्मर धीरे-धीरे खुद को खाद्य व तेल कंपनी के तौर पर स्थापित कर रही है जबकि पहले वह खाद्य तेल का अहम ब्रांड था। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल कारोबार 28,000 करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें खाद्य उत्पादों का योगदान 5 से 10 फीसदी रहा जबकि सबसे ज्यादा योगदान खाद्य तेल उत्पादों का रहा।

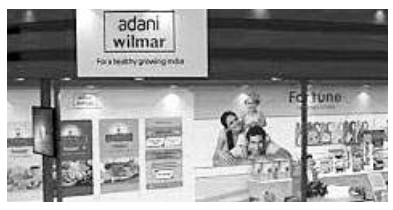

साल 2020 के आखिर तक 80 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल करेगी कंपनी

'बैंकों के लिए जोखिम है परिसंपत्ति गुणवत्ता के नियमों में नरमी'

अभिजित लेले
मुंबई, 10 फरवरी

परिसंपत्ति गुणवत्ता के नियमों में नरमी से प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी देते हुए रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि यह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में परिसंपत्ति के वर्गीकरण की गुणवत्ता व पारदर्शिता में इजाफा करने की आरबीआई की कोशिश से धीरे-धीरे दूर हटने का संकेत देता है। फिच ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे व मझोले उद्यमों के लिए एक बार की पुनर्गठन योजना की खातिर 12 महीने का समय दिया है। साथ ही बैंकिंग नियामक ने कुछ निश्चित रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण में छूट की घोषणा की है, जो कर्ज की पहचान की नियामक की मुहिम को हलका करता है। ऐसे नियामकीय कदम से जोखिम पैदा होने की आशंका है क्योंकि इसके तहत कर्ज में इजाफे के लिए आक्रामक तरीका अपनाया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसी सहनशीलता का विस्तार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में होगा या नहीं। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में नकदी संकट और अर्थव्यवस्था में नरमी का एमएसएमई व रियल एस्टेट क्षेत्रों पर असर को देखते हुए ऐसा होने की संभावना ज्यादा है।

फिच ने कहा, हाल के वर्षों में बैंकों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) को उधार देने को प्राथमिकता दी है, जो रियल एस्टेट और एमएसएमई क्षेत्रों को काफी ज्यादा कर्ज देते हैं। इसे अतिरिक्त नकदी की तैनाती के तरीके के रूप में देखा गया, वहीं ऐसे क्षेत्रों में सीधे तौर पर कर्ज को सीमित करने के तौर पर भी।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स का बाजार पूंजीकरण 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार

डीमार्ट खुदरा श्रृंखला की परिचालक एवेन्यू सुपरमार्ट्स का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया क्योंकि कंपनी के शेयर में 8.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, राधाकृष्ण दमानी प्रवर्तित कंपनी अब नेस्ले इंडिया और बजाज फिनसर्व से ज्यादा मूल्यवान हो गई है। सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियों की सूची में अब इस रिटेलर का स्थान 18वां है। कंपनी का शेयर 2,484 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने क्यूआईपी की कीमत 2,049 रुपये प्रति शेयर तय है। क्यूआईपी से करीब 4,100 करोड़ रुपये जुटाने के लिए कंपनी ने 2 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं। निवेश बैंकरों ने कहा कि शेयर बिक्री को निवेशकों की भारी प्रतिक्रिया मिली। क्यूआईपी के बाद कंपनी में प्रवर्तक हिस्सेदारी करीब 2.8 फीसदी घटेगी। *बीएस*

आंकड़े जुटाने को धन देगा वित्त आयोग

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 10 फरवरी

पंद्रहवां वित्त आयोग अपनी दूसरी रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिए अनुदान देने की सिफारिश करेगा। इसका मकसद भारत में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह और उनके मिलान में सुधार करना है। यह विभिन्न सेक्टरों के अनुदान में होगा, जिसे 15वें वित्त आयोग ने अपनी आगामी रिपोर्ट में देने का वादा किया है, जो कुछ मानकों को हासिल करने के लिए केंद्र व राज्यों को दिया जाएगा। यह कदम ऐसे समय सामने आ रहा है, जब भारत के आधिकारिक आंकड़ों की व्यापक आलोचना हो रही है।

बजट वाले दिन 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। इसमें कर बंटवारे वाले खाते से राज्यों को 41 प्रतिशत देने की सिफारिश की गई है, जो अभी 42 प्रतिशत दिया जाता था। यह हाल में गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वजह से किया गया है, जो अब केंद्र के हिस्से से धन पाएंगे और 29 राज्यों की जगह अब 28 राज्यों के बीच कर का विभाजन होगा।

2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान आवंटन से संबंधित वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर में पेश किए जाने की संभावना है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा है, 'नीतियां बनाने के साथ उन्हें लागू करने व उनकी निगरानी के लिए विश्वसनीय व भरोसेमंद आंकड़े अहम है। मोस्पी ने आंकड़ों के संग्रह को लेकर विस्तृत ब्योरा पेश किया है, जो हमारे विचारार्थ है।' मोस्पी केंद्र सरकार का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है। इसमें कहा गया है, 'प्रस्ताव के आधार पर आयोग ने सांख्यिकी के लिए अनुदान मुहैया कराने की योजना बनाई है, जो सशर्त होगा और कुछ उपलब्धियां हासिल करने के आधार पर इसे जारी किया जाएगा।' इन उपलब्धियों में जिला घरेलू उत्पाद आंकड़े पूरा करना और उसे जारी करना, संबंधित आंकड़े अग्रिम जारी करना, आंकड़ों के संग्रह में सुधार, टिकाऊ विकास के उद्देश्यों के लिए राज्य निगरानी ढांचा आदि शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'वर्ष 2020-21 के दौरान मोस्पी और राज्य सरकारें दिशानिर्देश बनाने, मानव संसाधन चिह्नित करने व उन्हें प्रशिक्षित करने और रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करने व 2021-22 और उसके बाद के लिए उपलब्धियां हासिल करने के लिए काम करेंगी।'

इस मकसद के लिए मिलेगा धन

- जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) के आंकड़ों का संकलन और उसे सालाना जारी करना

- आईआईपी और सीपीआई के राज्य सूचकांक का संकलन और उसे हर महीने जारी करना
- नैशनल एसडीजी डैशबोर्ड के साथ इसे अद्यतन करने के लिए राज्य निगरानी ढांचा तैयार करना
- मासिक, तिमाही और सालाना एडवांस रिलीज कैलेंडर का प्रकाशन
- राष्ट्रीय नमूना सर्वे में सहभागिता और उप-राज्य/जिला स्तर पर अनुमान को सर्वे पूरा होने के एक साल के भीतर जारी करना
- कंप्यूटर की मदद से डेटा जुटाने में तकनीक का इस्तेमाल
- प्रस्तावित नैशनल बिजनेस रजिस्टर के गतिशील उन्नयन को लागू करना

स्रोतः 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

'वित्त आयोग को स्थायी बनाने पर विचार नहीं'

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि सरकार का वित्त आयोग को स्थायी दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है। इस समय सरकार एक नियत काल के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करती है।

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ठाकुर ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी आयोग को स्थायी दर्जा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। निचले सदन में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा, 'नहीं, सरकार वित्त आयोग को स्थायी दर्जा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।' वित्त आयोग के प्रमुख दायित्वों में केंद्र व राज्य सरकारों के वित्त का मूल्यांकन करना, उनके बीच कर साझा करने के बारे में सिफारिश करना, राज्यों के बीच इन करों के विभाजन के सिद्धांत बनाना शामिल है। सरकार ने नवंबर में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दिया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व नौकरशाह एनके सिंह कर रहे हैं। मूल रूप से आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2019 के अंत तक खत्म होने वाला था। *एजेंसियां*

न्यायालय पहुंची एमेजॉन

पीरजादा अबरार और
नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 10 फरवरी

ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एमेजॉन ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। सीसीआई ने कंपनी के कुछ कारोबारी तरीकों में जांच के आदेश दिए हैं।

पिछले महीने सीसीआई ने व्यापार संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ (डीवीएम) की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत पर जांच के आदेश दिए थे। शिकायत में कंपनी पर स्मार्टफोन की बिक्री में भारी छूट देने और चुनिंदा विक्रताओं के साथ साझेदारी करने का आरोप लगाया गया है। जांच के दायरे में एमेजॉन के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी फ्लिपकार्ट को भी शामिल किया गया है। फ्लिपकार्ट का स्वामित्व अब वॉलमार्ट के पास है।

आज दाखिल की गई अपनी याचिका में एमेजॉन ने न्यायालय से सीसीआई की कार्रवाई पर एक अंतरिम रोक लगाने की मांग की है क्योंकि इस जांच से ई-कॉमर्स कंपनियों की प्रतिष्ठा/साख को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी।

इसमें कहा गया है, 'सीसीआई का आदेश प्रथम दृष्टया बिना किसी सोच विचार के दिया गया है जिसका याची कंपनी एमेजॉन पर गंभीर असर होगा। जांच के परिणाम विकृत, मनमाना और कानूनी तौर पर अपुष्ट हैं।' एमेजॉन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण याचिका लगाई है। इसके तहत निचले न्यायालय या प्रशासनिक एजेंसी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की मांग की जाती है।

एमेजॉन इंडिया का पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक में स्थित है और इसीलिए रिट याचिका कर्नाटक उच्च न्याल में दाखिल की गई है जिसमें सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले सीसीआई ने ई-कॉमर्स की ओर से भारी छूट देने के मामले का अध्ययन करने के बाद कहा था कि यह कोई प्रतिस्पर्धा का मुद्दा नहीं है।

डीवीएम ने प्रतिस्पर्धा नियामक को दिए अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्मों पर कई तरह की छूट देने के साथ ही विक्रेताओं को इन्वेंट्री मुहैया कराकर कीमत को प्रभावित कर रहे हैं। उसने शिकायत में आगे कहा था कि विशिष्ट व्यवस्थाएं, भारी छूट और एमेजॉन तथा फ्लिपकार्ट की ओर से तरजीही सूचीबद्धता का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धा का गला घोंटने के लिए अपवर्जनात्मक तरकीब के तौर पर किया जा रहा है जिसका प्रतिस्पर्धा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

हालांकि, नई दिल्ली स्थित विशिष्ट प्रौद्योगिकी कानून फर्म टेकलेगीस एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसिटर्स में प्रबंध पार्टनर सलमान वारीस के मुताबिक एमेजॉन को तुरंत राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि रिपोर्ट से पता चलता है कि डीवीएम पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक प्रतिवाद दायर कर चुका था।

नतीजतन, एमेजॉन न्यायालय में बहस होने से पहले ही जांच के आदेश पर तुरंत स्थगन हासिल कर पाने में सफल नहीं होगी। वारिस ने कहा, 'लंबी अवधि में देखें तो इस तरह की कार्रवाई से केवल इन ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कारोबारी सुगमता ही जटिल होगी और एक नियामकीय कानूनी नीति परिपेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे बहुत सकारात्मक संकेत नहीं जाएगा।'

उन्होंने कहा, 'इससे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे कुछ अनुचित तरीके भी सामने आ सकते हैं जिसका आरोप लगाया जाता है लिहाजा लंबी अवधि में उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें अपने कारोबारी मॉडल में जरूरी बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।'

खुदरा ऋण पर बैंकों को 5 साल की राहत

पृष्ठ 1 का शेष...

आरबीआई पिछले कुछ समय से इस कोशिश में लगा है। इसके पीछे उसकी सोच बैंकों के लिए फंड की लागत कम करना है।

एक अर्थशास्त्री ने कहा, 'इसके साथ-साथ दीर्घकालिक रीपो परिचालन(एलटीआरओ) से बैंकों के लिए जमा दरों में कमी किए बिना फंड की लागत कम हो सकती है।' रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में कहा कि बैंक रीपो दर पर एक और तीन साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये तक की नकदी की सुविधा ले सकते हैं।

बैंकों का अब तक तर्क रहा है कि अगर जमा दरों में कटौती नहीं होगी तो वे उधारी दरों में कमी नहीं कर सकते हैं। जमा दरों में कमी से ग्राहक ज्यादा रिटर्न के लिए कहीं और का रुख कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि एलटीआरओ बैंक के लिए जमा जैसा उत्पाद है। केंद्रीय बैंक के लिए इस तरह की योजनाओं की घोषणा के अपने जोखिम भी हैं क्योंकि इससे ब्याज दरों का चक्र पलट सकता है और दरें ऊपर जा सकती हैं।

एक अर्थशास्त्री ने कहा, 'अगर बैंक एलटीआरओ से पैसे लेते हैं या सीआरआर में छूट से उन्हें बचत होती है और वे कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो यह भी एक तरह की उधारी है और इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलनी चाहिए।'

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई सीआरआर रियायत और एलटीआरओ परिचालन को बढ़ा सकता है। मौद्रिक नीति के एक विशेषज्ञ ने कहा कि मौद्रिक नीति की कोई सीमा नहीं है। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने तक आरबीआई नियमों में बदलाव जारी रखेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में आगे नकदी की समस्या होने की आशंका नहीं है क्योंकि विदेशी निवेशक हमेशा यहां ज्यादा प्रतिफल की तलाश में रहेंगे लेकिन आरबीआई के गैर परंपरागत उपायों से नकदी अल्पकालिक बॉन्ड निवेश से दीर्घकालिक बॉन्ड निवेश की तरफ जाएगी। एक विशेषज्ञ ने कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आरबीआई एक नपातुला जोखिम ले रहा है।

व्हाट्सऐप पेमेंट के खिलाफ याचिका

उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर व्हाट्सऐप पेमेंट सर्विस के भारत में कठित परीक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई है। देश में 10 लाख उपभोक्ताओं वाले इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप द्वारा कराए जा रहे इस परीक्षण के बारे में याचिका में कहा गया है कि उन्हें परीक्षण की वस्तु नहीं बनाया जा सकता है।

सेंटर फॉर एकाउंटिबिलटी ऐंड सिस्टमेटिक चेंज नाम के एक एनजीओ ने इसके पहले शीर्ष न्यायालय से संपर्क कर दावा किया था कि व्हाट्सऐप ने रिजर्व बैंक की अधिसूचना का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें डेटा के स्थानीयकरण के मानक बताए गए हैं। इसने कहा है, 'व्हाट्सऐप रिजर्व बैंक के डेटा के स्थानीयकरण के मानकों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन वह अपने पेमेंट सिस्टम के लिए भारत के 10 लाख उपभोक्ताओं पर बेटा टेस्टिंग जारी रखे हुए है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि व्हाट्सऐप पे ग्राहकों के बीच शुरू की जाएगी, जबकि न्यायालय के समक्ष व्हाट्सऐप ने रिजर्व बैंक के डेटा के स्थानीयकरण मानकों के पूर्ण अनुपालन के बारे में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।' *एजेंसियां*

बीएस सूडोकू 3661 | परिणाम संख्या 3660

8	6		3					
		3					4	
			5	7		3		6
6		1	8					
		7	9		6	5		
					2	6		8
2		4		9	1			
	9					1		
					3		6	7

7	8	1	9	5	6	3	4	2
3	6	4	1	2	7	5	8	9
2	9	5	3	4	8	7	1	6
4	1	7	5	3	9	2	6	8
8	5	3	4	6	2	9	7	1
6	2	9	7	8	1	4	3	5
5	7	6	8	9	4	1	2	3
1	3	2	6	7	5	8	9	4
9	4	8	2	1	3	6	5	7

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान
★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2010/2020, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1425/1525,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2010/2015, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4250, लालमती 3150/3200, चावल (सोना) 2700/2750,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1345, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1418, फ्लैक 1365, डीएमओ 983, टरपीन लैस बोल्ड 1440

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1080/1180, खुरपा 980/1000,चाकू 1050/1100, रसकट 880/900, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3250,

हापुड़
गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/960, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4250, खलः सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2350, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1750/1760, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3775/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4225/4230,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3700/3750, जौ 2100/2125,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 6900/7000, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1800/1825, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)112, राइसब्रान (अखाद्य) 109, खल सरसों 1900, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1100, लाल 1100, कंटीन्यूअस 1225,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 8000/8700, अरहर दाल 7400/7900, उड़द साबुत 7300/8400, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 8700/9300, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5300/5400,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 5800/5900, सेला 5250/5300, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4000/4050, चावल 1509 सेला 4950/5000, धानः शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4030/4060, हरियाणा 4000/4020, राजस्थान 3950/4020, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 1900/2000,

फाजिल्का
गेहूं 2040/2050, सरसों 4025/4125 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 4300/4400, कपास नरमा (क्विं.) 5050/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2020/2040, चावल परमल कच्चा 2325/2365, से ला 2260/2310, मक्की यूपी 2100/2120, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4675/4725, दाल चना 5050/5125, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7500/8900,चीन 8500/9000, शर्मिली 6000/7300,

करनाल
गेहूं दड़ा 2025/2040, बासमती चावल 6200/6300, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2600/2640, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 4950/4975, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3700/3750, जौ 1840/1850, सरसों 3850/3900, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/480, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2150/2250, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8650/8700, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3700/3750, बाजरा 1700/1750 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 306

गैरजरूरी कदम

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) डॉजियर दुनिया के सर्वाधिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था से आया प्रतीत होता है। 42 वर्ष पुराना यह अधिनियम किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की इजाजत देता है ताकि वह इस तरह काम न कर सके जो राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो। यह गिरफ्तारी दो वर्ष तक के लिए हो सकती है।

मुफ्ती और अब्दुल्ला ने नजरबंदी के छह महीने पूरे किए हैं। उनके खिलाफ यह डॉजियर विचित्र है। बिना ठोस प्रमाण के दोनों नेताओं के खिलाफ लगे आरोप एक जीवंत लोकतंत्र में नेताओं की सामान्य गतिविधियों पर लगे आरोप हैं। मसलन, मुफ्ती को बिना किसी स्पष्टीकरण के 'पिता की प्यारी पुत्री' (क्या पिता का करीबी होना सुरक्षा के लिए खतरा है?) कहा गया है जो खतरनाक और कुचक्र में माहिर और हड़पने वाली प्रकृति की हैं। इसके सबूत के रूप में उन वक्तव्यों को पेश किया गया है जो उन्होंने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 और 35 ए समाप्त करने पर दिए थे। संविधान के ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर नामक पूर्व राज्य को विशेष दर्जा देते थे। मुफ्ती ने केंद्र के कदम की तुलना बारूद के ढेर में आग लगाने से की थी और तीन तलाक को आपराधिक बनाए जाने के खिलाफ ट्वीट किए थे। ऐसी बातें तो तमाम टिप्पणीकारों ने की थी। क्या इस बात से वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गईं?

डॉजियर में कुछ गोपनीय रिपोर्टों के हवाले से यह भी कहा गया है कि वह अलगाववादियों से मिलीभगत रखती हैं। गोपनीय रिपोर्ट का हवाला तभी दिया जाता है जब कोई ठोस प्रमाण नहीं होता। शायद उनकी इस मांग को देश के खिलाफ माना गया हो कि मौत के बाद आतंकियों के शव के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। एक असहज करने वाला तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2016 से 2018 तक इन्हीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी से गठबंधन किया था। अब्दुल्ला के खिलाफ सबूत के रूप में भी अनुच्छेद 370 और 35 ए के समर्थन में उनके भाषणों और उनके इस वक्तव्य को पेश किया कि अनुच्छेदों को खत्म करने से जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे पर बहस फिर शुरू हो जाएगी। यह कहा गया है कि उन्हें इसलिए बंदी बनाया गया है क्योंकि उनमें लोगों को किसी भी काम के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया गया है कि वह आतंकी गतिविधियों और चुनाव के बहिष्कार के चरम दिनों में भी लोगों को वोट देने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर लेते थे। यह अत्यंत विसंगतिपूर्ण बात है।

कहा जा सकता है कि दोनों नेता अपने ही हथियार के शिकार हो गए। क्योंकि राज्य सरकार सन 1978 में पारित होने के बाद से आए दिन इस कानून का प्रयोग करती रहती थी। परंतु केंद्र ने जिन सबूतों पर कार्रवाई की है वे यही बताते हैं कि यह जम्मू कश्मीर का दर्जा बदलने के निर्णय की आलोचना के प्रतिक्रिया में किया गया। यह भी ध्यान देने लायक बात है कि उसने पीएसए अधिनियम में 2018 में किए गए संशोधन का पूरा इस्तेमाल किया। इसके तहत लोगों को राज्य के बाहर भी बंदी बनाया जा सकता है। यह सब सन 1919 के रॉलेट ऐक्ट की मुखालफत करने वालों के प्रति ब्रिटिशों की प्रतिक्रिया जैसा है। अंतर केवल यह है कि वह दमन एक औपनिवेशिक शक्ति ने किया था। केवल भाजपा ही नहीं देश की तमाम सरकारें ऐसे कदम उठाती रही हैं। सन 1971 में पारित विवादास्पद आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) को याद कीजिए। दुखद है कि यह परंपरा जारी है। यदि सरकार की आलोचना का नागरिक अधिकार कानून व्यवस्था की चुनौती बन जाए तो लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य दांव पर लग जाता है।

अजय मोहंती

कर राजस्व लक्ष्य में दूसरी बार कटौती संभव

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 9 प्रतिशत घटा दिया। अगले साल अगर इन आंकड़ों में और संशोधन किए गए तो यह सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। बता रहे हैं **ए के भट्टाचार्य**

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि इसमें प्रस्तावित कर राजस्व के आंकड़े वास्तविकता से दूर हैं। यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बजट में प्रस्तावित कर राजस्व का लक्ष्य हासिल होता मुमकिन नहीं दिख रहा है? शुरुआत केंद्र के शुद्ध कर राजस्व के आंकड़ों से करते हैं। सरकार की कुल प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी आधी से अधिक होती है और इसके मद्देनजर संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत तक सीमित करने की सरकार की क्षमता पर नकारात्मक असर हो सकता है। चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए बजट के संशोधित अनुमान में शुद्ध कर राजस्व का आंकड़ा 1.45 लाख करोड़ रुपये घटा कर 15.04 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। जुलाई में बजट अनुमान के16.49 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से यह कम है।

कुल मिलाकर इस 9 प्रतिशत की कमी से राजस्व के वास्तविक आंकड़े का अनुमान लगाने की सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अर्थव्यवस्था की हालत और वर्ष के शुरू में कर जुटाने के कर विभाग के वादों के मद्देनजर कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। हालांकि इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि क्या पहले से कम किए जा चुके इन आंकड़ों में और कमी की जाएगी? अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक या 2019-20 के पहले नौ महीनों में जुटाए शुद्ध कर राजस्व संग्रह के आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्र का शुद्ध कर राजस्व महज 9.05 लाख करोड़ रुपये है। 1 फरवरी को बजट में पेश संशोधित आंकड़ों के अनुसार यह कुल कर राजस्व का करीब 60 प्रतिशत है।

दूसरे शब्दों में कहें तो चालू वित्त वर्ष के बाकी तीन महीनों में अतिरिक्त 40 प्रतिशत (6 लाख करोड़ रुपये) कर संग्रह होना है। यह आंकड़ा पहले नौ महीनों में प्राप्त संग्रह की औसत मासिक दर के मुकाबले दोगुना है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या ऐसी उम्मीदें उचित हैं? इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वित्त वर्ष 2018-19 पर विचार करते हैं। सरकार अप्रैल-दिसंबर 2019 में पूरे वर्ष के कुल कर राजस्व लक्ष्य का 9.36 लाख करोड़ रुपये (71 प्रतिशत) संग्रह कर पाई। इसका मतलब हुआ कि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में पूरे वर्ष के कुल शुद्ध कर राजस्व का महज 29 प्रतिशत आंकड़ा हासिल किया गया।

इस वर्ष संग्रह दर 40 प्रतिशत ले जाना एक चुनौती होगी। वित्त वर्ष 2019-19 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही थी, जिससे टैक्स बॉयंसी में तेजी दिखी थी। वर्ष 2019-20 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर केवल 7.75 प्रतिशत है। ऐसे में कर विभाग लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सा नुस्खा आजमाएगा? वास्तव में पिछले पांच वर्षों में केवल एक बार वर्ष की अंतिम तिमाही में केंद्र के शुद्ध कर राजस्व की संग्रह दर पूरे वर्ष के संग्रह का 40 प्रतिशत रही थी। 2014-15 में ऐसा हुआ था। उस वर्ष अंतराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाने से लाभ मिला था। इसके अलावा तब नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर करीब 11 प्रतिशत रही थी।

वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में पूरे वर्ष के शुद्ध कर राजस्व संग्रह लक्ष्य का करीब 28 प्रतिशत ही संग्रह हो पाया। इसे पिछले दो वर्षों में भी अंतिम तिमाही में संग्रह दर 32 प्रतिशत (2016-17) और 34 प्रतिशत (2015-16) प्रतिशत के साथ बेहतर रही थी। हालांकि यह आंकड़ा कभी भी 40 प्रतिशत के इर्द-गिर्द नहीं रहा, जिसकी आवश्यकता चालू वित्त वर्ष में होगी। उदाहरण के लिए अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शुद्ध कर संग्रह दर 2018-19 या 2017-18 की तरह ही रहती है। इस हिसाब से जनवरी-मार्च 2020 में शुद्ध कर संग्रह 4.2 से 4.4 लाख करोड़ रुपये के बीच रहेगा। इस तरह, 2019-20 के दौरान पूरे वर्ष के लिए शुद्ध कर संग्रह करीब 13.3 से 13.4 लाख करोड़ रुपये रहेगा।

इसका सीधा मतलब यह होगा कि कर राजस्व में 1.6 लाख करोड़ से 1.8 लाख करोड़ रुपये की और कमी आ जाएगी। कर कमी से बचने का एक ही तरीका है और उसके लिए कर विभाग को 2014-15 का प्रदर्शन दोहराना होगा। हालांकि इस तरह का प्रदर्शन पांच वर्षों में केवल एक बार ही दिखा है। कर राजस्व संग्रह में और कमी आने से 2020-21 के राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल असर होगा जब शुद्ध कर संग्रह 16.36 करोड़ रुपये होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जैसा कि पहले देखा गया है, अगर चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शुद्ध कर संग्रह की रफ्तार 2017-18 या 2018-18 की चौथी तिमाही की तरह ही रहती है तो 2019-20 में कुल संग्रह केवल 13.26-13.41 लाख करोड़ रुपये रहेगा।

इसका नतीजा यह होगा कि मौजूदा अनुमानित 9 प्रतिशत के मुकाबले शुद्ध कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य 2020-21 के लिए बढ़कर 22 से 23 प्रतिशत हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आयकर विभाग की चुनौतियों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य में 223 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, जिसके मद्देनजर 2020-21 के लिए बजट अनुमान और चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। सरकार के कर राजस्व अनुमानों के साथ आ रही दिक्कतें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फरवरी 2019 में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो स्थिति बदतर हो गई। उस समय संशोधित अनुमान में तय लक्ष्य कर विभाग के वाजिब एवं हासिल हो सकने वाले लक्ष्य से अधिक था। एक वर्ष बाद 2018-19 के लिए वास्तविक शुद्ध कर संग्रह के आए आंकड़े दर्शाते हैं कि 14.84 लाख करोड़ रुपये संग्रह के लक्ष्य के मुकाबले वे 11 प्रतिशत कम यानी 13.17 लाख करोड़ रुपये रहे थे।

2019-20 के बजट में प्रस्तुत शुद्ध कर संग्रह के संशोधित अनुमान अपेक्षाकृत वास्तविकता के करीब थे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में शुद्ध कर संग्रह के 16.49 लाख करोड़ रुपये का बजट अनुमान 9 प्रतिशत घटा कर 15.04 लाख करोड़ रुपये कर दिया। अगले साल अगर इन आंकड़ों में और संशोधन किए गए तो यह सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है।

प्रकृति के साथ हमारे कुत्सित संबंधों से विषाणु की समस्या

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

इसे कीड़े का प्रतिशोध कहें। नए कोरोनावायरस ने चीन की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी नहीं कर सके। इस वायरस को 2019-एनसीओवी नाम दिया गया है। इसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया है, उत्पादन ठहर गया है, शहरों की रफ्तार थम गई है और लोगों को अलग-थलग कर दिया गया है। इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संभवत: अब तक के सबसे व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इसे वायरस के खिलाफ जनता की लड़ाई बताया है। लेकिन चिंताजनक सवाल यह है कि करीब एक महीने में इससे 900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 40 हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं। आखिर इसका खात्मा कब होगा? यह वायरस दो सप्ताह से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है। इस दौरान संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी मृत्यु दर कम है। लेकिन इसके फैलने का खतरा बहुत अधिक है क्योंकि यह हवा के जरिये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके प्रसार को रोकने का यही तरीका है कि संभावित मरीज को अलग-थलग रखा जाए।

लेकिन आपस में जुड़ी दुनिया में इसके क्या मायने हैं? एक ऐसी दुनिया जिनमें सीमा के आरपार लोगों की आवाजाही और व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस तथ्य पर गौर कीजिए। दुनिया में पहली बार 2003 में इस तरह का स्वास्थ्य संकट देखने को मिला था जब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) का कहर बरपा था तो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चीन की हिस्सेदारी केवल 4 फीसदी थी। आज यह 16 फीसदी है। इसी से दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चीन की अहमियत को समझा जा सकता है। यह दुनिया में सस्ते सामान की आपूर्ति श्रृंखला है। इसलिए चीन में स्वास्थ्य संकट से पूरी दुनिया में कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही अब दुनिया में बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, इसलिए वायरस के तेजी के फैलने की आशंका भी ज्यादा है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस संकट से निपटने के लिए सरकारें हरसंभव प्रयास कर रही हैं। लेकिन इससे हमारी साझा कमजोरी दिखती है कि कैसे एक आम सर्दी जुकाम दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

यह 2003 के सार्स और 2012 में फैले मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (मर्स) से ज्यादा गंभीर है। इन सभी मामलों में चमगादड़ में पाया जाने वाला वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। सार्स के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पाया कि वायरस सिवेट कैट, रैकून डॉग और बिज्जू के जरिये इंसानों में आया। 2019-एनसीओवी के मामले में अब तक यह साफ नहीं है कि यह इंसानों में कैसे आया। कहा जा रहा है कि कि जहां से इसकी शुरुआत हुई वहां के स्थानीय बाजार में चमगादड़ नहीं बेचा जाता है। वैज्ञानिक अभी इस बारे में जांच कर रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इंसानों में जीवों से होने वाली बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें स्वाइन फ्लू से एवियन इनफ्लूएंजा शामिल हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसान में फैल रही हैं और महामारी का रूप ले रही हैं।

सच्चाई यह है कि प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे कुत्सित संबंधों के कारण वायरस जानवरों से इंसानों में आ रहे हैं। एक तरफ हम हर तरह के रसायन और जहरीले पदार्थों को अपने खाद्य पदार्थों में मिला रहे हैं। इससे हम खाद्य पदार्थों को पोषण के बजाय बीमारी का स्रोत बना रहे हैं। जानवरों और यहां तक कि फसलों को ऐंटीबायोटिक की खुराक दी जा रही है। इसकी वजह बीमारी पर काबू पाना नहीं है बल्कि जानवरों का वजन बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इससे इंसान की प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ, हम अपने भोजन में उन तरीकों को बढ़ा रहे हैं जो रोग बढ़ाने के अनुकूल हैं। जानवरों का मांस बड़े-बड़े कारखानों में प्रसंस्कृत किया जा रहा है जो दुनिया में तेजी से संक्रमण का स्रोत बन रहा है। याद रखिए कि स्वाइन फ्लू की शुरुआत मैक्सिको में सूअर के मांस का प्रसंस्करण बनाने वाले कारखानों से हुई थी। इससे पानी प्रदूषित हुआ था। इंसान और जानवरों के पर्यावास के बीच सीमाओं के टूटने से इस तरह की बीमारियों की संख्या बढ़ेगी। आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया और वैश्वीकरण के दौर में इस तरह का संक्रमण तेजी से फैलेगा।

दुनिया में जिस तरह से कारोबार होता है, वह भी सवालों के घेरे में है। सच्चाई यह है कि बीमारी से जलवायु परिवर्तन तक दुनिया की कमजोरी बढ़ेगी। पिछले तीन दशकों में दुनिया ने एक एकाकी व्यापार व्यवस्था के निर्माण में निवेश किया जिसमें स्थानीय या क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए कोई जगह नहीं है।

गरीबों की जोखिम प्रबंधन व्यवस्थाओं से हमें यह सीखना चाहिए कि विविधता अस्तित्व की कुंजी है। हमारे किसान हमेशा फसल और पशुपालन के जरिये कम से कम जोखिम उठाते हैं। वे तरह-तरह की फसलें उगाते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर इलाकों में 50 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। उन्होंने उन कारकों पर अपनी निर्भरता कम की जिन पर उनका वश नहीं था। इसके बजाय उन्होंने ज्यादा लचीली स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया। अब मैं जानती हूं कि हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पीछे नहीं मोड़ सकते हैं और इस तरह इस विश्व व्यापार व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यह मुनाफे वाली है और हर कोई विश्व आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में कुछ झटके हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हमें वैश्वीकरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करना चाहिए। आइए पहले स्थानीयकरण पर काम करके शुरुआत करें।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं।)

कानाफूसी

त्वरित प्रतिक्रिया

दिल्ली में गत शनिवार को करीब 15 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। परंतु वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स इसे लेकर कुछ अलग ही सोच रही थी। कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि आज शनिवार है, यानी अपना पसंदीदा शो देखते हुए हल्की-फुल्की झपकी ली जा सकती है। इस पर आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तत्काल प्रतिक्रिया दी और कहा कि नहीं पहले जाइए और मतदान कीजिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बार-बार आह्वान के बावजूद दिल्ली में बहुत अधिक मतदान नहीं हुआ। हालांकि देर शाम इसमें तेजी आई थी और उसे लेकर अब विवाद भी हो रहा है।

नई रणनीति

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पिछले वर्ष पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में नई जान फूंकने की कोशिश शुरू किए जाने के बाद से ही पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है। पहले पार्टी ने संगठन ढांचे में बदलाव किया और नए सदस्यों को शामिल किया और बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। अंतिम चरण में पार्टी ने अपने मीडिया पैनल को नए सिरे से गठित किया है और उन लोगों को जगह दी है जिन्हें पहले हाशिये पर रखा गया था। मीडिया शाखा में उन दिग्गजों को शामिल किया गया है जिनके पास अनुभव है और जिनके मीडिया घरानों से अच्छे रिश्ते हैं। माना जा रहा है कि यह रणनीति काम आएगी।

आपका पक्ष

चीन से आयात कम करने की जरूरत

सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ व्यापार के लिए निर्भर हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि देश के विकास और विश्वव्यापी समस्याओं के लिए एकजुट होना चाहिए। लेकिन सभी देशों का एकजुट होना और एक-दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान भी नहीं है। भारत दूसरे देशों, खासतौर पर अपने पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार करने के मामले में गंभीरता से कदम नहीं उठाता है। इस कारण भारत को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण भारत आज सोने की चिड़िया नहीं रह गई है। भारत की पराधीनता का कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना और गुलामी की जंजीरों जकड़ा जाना था। अगर महात्मा गांधी ने भारतीयों को स्वदेशी के प्रति जागरूक नहीं किया होता तो आज शायद भारत स्वतंत्र नहीं हुआ होता। आज एक बार फिर भारत

विदेशी सामान के मोह में फंसता जा रहा है। खासतौर पर चीन का बड़ा बाजार भारत बन गया है। चीन से ज्यादा आयात होने पर भारत अनजाने में चीन की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है और साथ ही अपने देश के उद्योग धंधों की बरबादी का कारण भी बन रहा है। भारत को विदेशी व्यापार के मामले में अन्य देशों की तरह ही समझौते

भारत को अन्य देशों से आयात करने के बजाय अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए

करने चाहिए, जिससे देश में रोजगार सृजन तथा अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसके बाद ही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

वायरस से बचाव के लिए सावधानी जरूरी

कोरोनावायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैल रहा है। चीन के बाद दूसरे देशों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वायरस का प्रमुख कारण समुद्री खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। चीन के वुहान शहर में कई लोगों की मौत हो चुकी है और सभी सरकारें इसे लेकर सावधानी बरत रही हैं। सरकारी प्रयासों के साथ हमें अपने स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए। किसी संदिग्ध मरीज से दूरी बनाने और सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पुराना खाना, विशेषकर समुद्री खाद्य पदार्थ खाने से बचें। इस वायरस से बचाव के लिए कोई विशेष दवाई उपलब्ध नहीं है और सावधानी बरतने तथा उचित इलाज से ही इससे बचा जा सकता है।

संदीप नेगी, नैनीताल

सिर्फ मास्क नहीं वायरस से बचाव

चीन में फैल रहे कोरोनावायरस को लेकर दुनियाभर में डर बढ़ रहा है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरने लगे हैं और अगर जा रहे हैं तो मास्क पहनकर। डॉक्टरों का कहना है कि अगर वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क पर निर्भरता बढ़ा दी जाए तो सही नहीं है। हर व्यक्ति के लिए मास्क वायरस से सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता। एन-95 रेस्पिरेटर मास्क कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। यह खासतौर पर उस स्थिति में प्रभावी होते हैं जब एक बीमार इंसान एन-95 रेस्पिरेटर मास्क का इस्तेमाल करे ताकि उसके खांसने और छींकने से दूसरे लोग बचे रह सकें। अगर वायु में संक्रमण फैलाने वाले वायरस हैं तो मास्क एक सीमा तक ही आपको सुरक्षित कर सकता है। कोरोनावायरस से बचने के लिए प्रभावी तरीका सार्वजनिक स्थान से आने के बाद हाथ अच्छी तरह धोना है।

तन्वी गुप्ता, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर भारत

भाषा
नई दिल्ली, 10 फरवरी

दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उपभोक्ता और आयातक देश भारत इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व दलहन दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत न केवल दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है बल्कि हम उत्पादन में और बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कई उपाय किए हैं मसलन न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और साथ ही किसानों को समर्थन के लिए दलहन की खरीद की जा रही है। देश ने 2018-19 के फसल वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान 2.34 करोड़ टन दलहन का उत्पादन किया। यह 2.6 से 2.7 करोड़ टन की घरेलू मांग से कम है। इस अंतर की भरपाई आयात से की गई। हालांकि, चालू साल में सरकार 2.63 करोड़ टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है।

तोमर ने कहा, 'दलहन न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी आवश्यक बन रही है। पहले हमें दलहन की भारी कमी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति सुधरी है।' मंत्री ने कहा, 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में शोध एवं विकास और उचित नीतिगत हस्तक्षेप से पिछले कुछ साल के दौरान दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल हुई है।'

उन्होंने कहा कि भारत दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। अभी ज्यादातर घरेलू जरूरत को देश में ही पूरा कर लिया जाता है। हम उत्पादन और बढ़ाएंगे और वैश्विक मांग को पूरा करने में भी मदद करेंगे।

कोरोनावायरस के कारण पश्चिमी देश परिधान के लिए चीन से बना रहे दूरी

भारत को मिल रहे कपड़ों के ऑर्डर

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 10 फरवरी

- चीन में कारखाने बंद होने की वजह से निर्यातकों को करना पड़ रहा सहायक सामग्री की कमी का सामना
- अधिक लागत के कारण घरेलू उद्योग को मौके का लाभ उठाने में आ रही दिक्कत
- भारत में तैयार कपड़ा उत्पादों, वस्त्रों और कपड़े का निर्यात कम से कम 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना
- लेकिन भारत में निर्मित परिधान बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया की तुलना में लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक महंगे
- सरकार ध्यान दे और कुछ कर लाभ प्रदान करे तो भारत के पास है बड़ा मौका

साल के इस समय पश्चिमी बाजार के खरीदार अगले सीजन के लिए परिधान निर्यातकों के साथ बातचीत की खातिर चीन की यात्रा करते हैं। लेकिन कोरोनावायरस की वजह से इनमें से ज्यादातर खरीदारों ने यह यात्रा रद्द कर दी है तथा भारत और अन्य देशों के निर्यातकों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। हालांकि यह अच्छी खबर है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। निर्यातकों का कहना है कि वे इस पूछताछ को ऑर्डर में तब्दील करने की हालत में नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी दामों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक अन्य बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में कुछ निर्यात इकाइयां अटकी हुई हैं क्योंकि वे चीन से सहायक सामग्री का आयात नहीं कर पा रही हैं।

चूंकि यह '2019 नोवेल कोरोनावायरस' (2019-एनकोवी) पूरे चीन में फैलता जा रहा है, इसलिए वहां कई कपड़ा कारखानों ने काम रोक दिया दिया है। इस कारण चीन से कच्चे माल और कपड़ा निर्यात में अड़चन आ गई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन टी राजकुमार ने कहा कि चीन में इस वायरस प्रकरण के कारण भारत में तैयार कपड़ा उत्पादों, वस्त्रों और कपड़े का निर्यात कम से कम 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है जिससे पिछले साल निर्यात में आई गिरावट से तत्काल राहत मिल सकती है।

लेकिन दूसरी तरफ लागत और क्षमता की समस्या भी है। फिलहाल बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों की तुलना में भारत में निर्मित परिधान लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक महंगे हैं। निर्यातकों का कहना है कि चूंकि इनमें से अधिकांश देश तकरीबन 90 से 95 प्रतिशत कच्चा माल आयात करने के लिए चीन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए अगर सरकार इस स्थिति पर तुरंत ध्यान दे और कुछ कर लाभ प्रदान करे तो भारत के पास अब भी कुछ मौका है।

कपड़े से निर्मित सामान और परिधानों पर वस्तु निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) के तहत दिया जाने वाला चार प्रतिशत का प्रोत्साहन हाल ही में कपड़ा उद्योग से वापस ले लिया गया है। यह 7 मार्च, 2019 से प्रभावी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एमईआईएस के तहत कपड़े से निर्मित सामान और परिधान निर्यात के लिए निर्यातकों को 31 जुलाई, 2019 तक दिए गए सभी प्रोत्साहनों की वसूली की जाएगी। पिछले साल अगस्त से चार प्रतिशत का एमईआईएस भी बंद किया जा चुका है। इसके अलावा पुराने राज्य शुल्क से राहत (आरओएसएल) योजना के अंतर्गत कुछ दावे अब भी लंबित पड़े हैं। इस योजना को 7 मार्च, 2019 से बंद कर दिया गया था।

मुंबई स्थित क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष और परिधान उद्योग के दिग्गज राहुल मेहता ने कहा कि अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और दामों को देखते हुए मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि हम इस तरह की पूछताछ का लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। सहायक सामान की आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा।

तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव टीआर विजय कुमार ने कहा कि भारतीय विनिर्माताओं द्वारा खरीदा गया सहायक सामान और इसका विनिर्माण वास्तव में प्रभावित हो रहा है। चीन के नव वर्ष के बाद से कोई डिलिवरी नहीं हुई है। वायरस की वजह से अब भी सभी इकाइयां बंद पड़ी हैं। इससे वास्तव में अपने ग्राहकों को समय पर डिलिवरी करने पर असर पड़ेगा।

करीब 10 प्रतिशत कपड़ा और 20 प्रतिशत सहायक सामान चीन से भारत आता है। एसोसिएशन का अनुमान है कि देश की कपड़ा इकाइयों द्वारा बटन, धातु के बटन, जिप, हैंगर और सुई सहित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सामान चीन से आयात किया जाता है क्योंकि यह सामान घरेलू और अन्य देशों से की जाने वाली आपूर्ति की अपेक्षा 40-50 प्रतिशत सस्ता होता है।

एसटी एक्सपोर्ट्स के प्रबंध निदेशक टी तिरुकुमारन ने कहा कि यही वह सबसे बड़ी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं क्योंकि बहुत-सा सहायक सामान चीन से आयात किया जाता है और अगर वे जल्दी से कारखाने नहीं खोलते हैं तो हमें बहुत देर हो जाएगी। दरअसल 21 जनवरी से गुआनझू में मेरी 12 चीजें अटकी हुई हैं।

एल्युमीनियम के प्राथमिक और द्वितीयक विनिर्माताओं में रार

आयात और दामों को लेकर दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप

जयजित दास
भुवनेश्वर, 10 फरवरी

- प्राथमिक उत्पादकों पर घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतों से 14 प्रतिशत अधिक दामों पर आपूर्ति करने का है आरोप
- एएआई ने स्पष्ट किया है कि एल्युमीनियम की कीमतें एलएमई की कीमतों और क्षेत्रीय उत्पादों के लाभ से जुड़ी होती हैं जो वैश्विक स्तर पर सभी उत्पादकों के लिए बेंचमार्क है

घरेलू बाजार से संबंधित मसलों को लेकर प्राथमिक और द्वितीयक एल्युमीनियम विनिर्माताओं के बीच रार पैदा हो गई है। इस विवाद का सबसे बड़ा कारण एल्युमीनियम आयात और इसके दाम हैं। एल्युमीनियम सेकंडरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एएसएमए) द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया जताते हुए एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) ने इनका क्रमवार खंडन करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है।

आरोप है कि प्राथमिक उत्पादक घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतों से 14 प्रतिशत अधिक दामों पर आपूर्ति कर रहे हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए एएआई ने स्पष्ट किया है कि एल्युमीनियम की कीमतें लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) की कीमतों और क्षेत्रीय उत्पादों के लाभ से जुड़ी होती हैं जो वैश्विक स्तर पर एल्युमीनियम के सभी उत्पादकों के लिए बेंचमार्क है।

एएआई ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि एल्युमीनियम निर्यातकों को कच्चे माल के लिए किए गए शुल्क या कर भुगतान के कुछ क्रेडिट के साथ-साथ निर्यात लाभ मिलते हैं। इसलिए एल्युमीनियम के मामले में निर्यात और घरेलू मूल्य का शुद्ध अंतर करीब दो से चार प्रतिशत होगा, न कि 14 प्रतिशत। इस आरोप में लाभ और ढुलाई जैसे अन्य शुल्क जोड़कर 14 प्रतिशत किया गया है ताकि गुमराह किया जा सके।

प्राथमिक उत्पादकों द्वारा अधिक लाभ मार्जिन प्राप्त करने वाले आरोप पर एएआई ने कहा है कि पूंजी प्रधान उद्योग होने की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉइड (आरओसीई) एक बेहतर बेंचमार्क रहेगा क्योंकि लाभ मार्जिन में अवमूल्यन और अधिक ब्याज लागत पर विचार नहीं किया जाता है। एल्युमीनियम के मौजूदा दाम प्रति टन 1,800 डॉलर हैं। दामों के इस स्तर पर 12 प्रतिशत से अधिक की पूंजी लागत के मुकाबले आरओसीई केवल पांच से छह प्रतिशत ही है। इसके अलावा घरेलू एल्युमीनियम उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है और लागत के लिहाज से प्रतिस्पर्धी होने के लिए जूझ रहा है।

इसके अलावा एएसएमए के इस तर्क पर कि दुनिया भर में एल्युमीनियम कबाड़ के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता है, एएआई ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि वैश्विक स्तर पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और एल्युमीनियम की अधिक खपत करने वाले देशों ने कबाड़ की रीसाइक्लिंग, उपयोग और आयात के लिए सख्त मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित किए हुए है।

एएसएमए भी एएआई द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए सामने आया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को लिखे अपने पत्र में एएसएमए ने कहा है कि हालांकि एल्युमीनियम के दाम एलएमई से जुड़े हुए हैं, लेकिन घरेलू बाजार में आयात मूल्य पर सामग्री बेचने से प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग को अतिरिक्त लाभ मिलता है।

इस पत्र में एएसएमए ने यह भी दावा किया है कि भारतीय प्राथमिक उत्पादकों की विनिर्माण लागत दुनिया में सबसे सस्ती है क्योंकि सरकार ने उन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले बॉक्साइट भंडार खंड आवंटित किए हुए हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए एसोसिएशन ने कहा कि पिछले साल नैशनल एल्युमीनियम कंपनी (नालको) को दुनिया में सबसे सस्ती विनिर्माता के रूप में चुना गया था।

एएसएमए ने अपने पत्र में कहा है कि प्राथमिक उत्पादकों के दबाव के कारण ऐसा हुआ था जब वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया था। वे घरेलू बाजार में 14 प्रतिशत अधिक दामों पर करीब 24 लाख टन प्राथमिक एल्युमीनियम की बिक्री कर रहे हैं और इस तरह सामान्य लाभ की तुलना में करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 10	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,693.5	-7.3	1,977.6	5.2
Copper	5,653.0	-5.0	6,297.6	2.7
Nickel	12,770.0	-21.1	13,605.0	-20.2
Lead	1,835.0	-12.7	2,103.9	-2.0
Tin	16,325.0	-2.1	17,391.9	-0.4
Zinc	2,152.5	-14.1	2,454.5	-11.2
Gold ($/ounce)	1,573.1*	7.8	1,770.1	7.0
Silver ($/ounce)	17.8*	5.9	20.2	4.3
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	53.6*	-14.8	54.3	-11.6
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-36.0	1.9	-33.6
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	196.7	7.6	291.0	-2.8
Maize	183.1*	1.7	262.1	-6.8
Sugar	428.7*	27.9	489.8	0.1
Palm oil	725.0	16.0	1,153.6	18.0
Rubber	1,280.4*	-12.0	1,904.0	6.9
Coffee Robusta	1,264.0*	-6.6	1,809.3	-4.8
Cotton	1,500.0	5.1	1,570.1	-1.0

* As on Feb 10, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71. 3 & 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	57.1	38309
Oil and Oilseeds	177.2	73758
Spices	2.2	10
Metal(Feb 07)		
Metal- non ferrous	5400.0	48534
Metal- precious	11033.6	373
Oil and gas(Feb 07)		
Gas	2555.0	49206
Oil	17266.3	3038

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	141.8	132476
Grains	267.7	95425
Oil and Oilseeds	765.0	442915
Others	187.7	63770
Pulses	84.6	44525
Spices	33.2	21534

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Gold (Apr 03)	40644.0	0.7
Gold Mini (Mar 05)	40563.0	0.7
Cardamom (Feb 14)	3589.1	0.4
Gold Petal (Feb 28)	4019.0	0.3
Gold Guinea (Feb 28)	32338.0	0.3
Losers (* % Change)		
Nickel (Feb 28)	940.7	-1.7
Zinc Mini (Feb 28)	169.9	-1.4
Crude Palm Oil (Feb 28)	740.1	-1.1
Copper (Feb 28)	430.9	-1.1
Natural Gas (Feb 25)	134.2	-1.0
Lead Mini (Feb 28)	144.7	-0.9
Cotton (Feb 28)	19020.0	-0.7

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Chana-Bikaner (Mar 20)	3938.0	1.7
Losers (* % Change)		
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6694.0	-3.5
Guar Seed 10 (Feb 20)	3816.0	-2.6
Soyabean Indore (Feb 20)	3942.0	-2.6
Coriander-Kota (Apr 20)	6167.0	-2.5
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1754.0	-2.2
Jeera Unjha (Mar 20)	13510.0	-1.5
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3844.0	-0.8
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1052.5	-0.7
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	3974.0	-0.5
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5884.0	-0.3
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	844.6	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1051.5	3.0
Aluminium Mum (May 29)	139.6	0.6
Zinc Mumbai (May 29)	173.3	0.6
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19020.0	0.5
Gold Ahm (Apr 03)	40644.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1190.4	-9.6
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3589.1	-6.0
Lead Min Mumbai (Feb 28)	144.7	-5.1
Lead Mum (May 29)	147.1	-3.5
Nickel Mumbai (Feb 28)	940.7	-3.1
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	169.9	-1.4
Gold Petal-Mumbai (Feb 28)	4019.0	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1915.0	4.1
Bajra-Delhi (Feb 20)	1915.0	1.9
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	743.9	1.5
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	18970.0	1.0
Moong-Merta City (Feb 20)	7627.0	0.9
Maize-Sangli (Feb 20)	1872.0	0.8
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1695.0	-20.7
Jeera Unjha (Mar 20)	13510.0	-6.3
Soy Bean Indore (Feb 20)	3942.0	-3.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6694.0	-2.7
Coriander-Kota (Apr 20)	6167.0	-2.1

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	105......(105)
Aluminium ingots /kg	141......(141)
Brass sheet cutting /kg	325......(325)
Brass utensil scraps/kg	310......(310)
Copper heavy scrap /kg	416......(415)
Copper utensil scraps/kg	390......(394)
Copper wire bar /kg	449......(450)
Lead ingots /kg	150......(150)
Nickel Cathodes /kg	970......(980)
Tin slabs /kg	1240......(1250)
Zinc slabs /kg	175......(175)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10208......(10236)
DCH - 32 /Qtl	11304......(11332)
Jaydhar /Qtl	9758......(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11051......(11079)
Source:Cotton Association of India	
Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	831......(843)
Castor Comm /10kg	821......(833)
Ricebran oil/10kg	820......(820)
Groundnut oil /10kg	1140......(1140)
Linseed oil /10kg	900......(900)
Karanji /10kg	800......(800)
Palm oil /10kg	845......(853)
Sunflower exp ref /10kg	885......(880)
Sunflower oil exp /10kg	830......(830)
Soyabean ref / 10kg	860......(863)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3602 ......(3382-3612)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	49.95......(50.32)
Brent Crude (UK)	53.59......(53.86)
Brent Crude (WTI)	50.32......(50.32)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.78......(1.86)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	282.81......(284.13)
Naptha spot /Rs/MT	45170......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950......(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40575......(40503)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40738......(40666)
Silver.999/ kg	46225......(46230)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18931.40	18784.80
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.50	138.65
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1910.00	1880.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1865.55	1840.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2142.35	2138.45
Cardamom-Vand. (I)*	1 K	3758.00	3758.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4020.35	3980.80
Castor Seed-Kadi (N)	X	3990.00	3990.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	3968.20	3949.15
Chana Delhi (N)	1 Q	4200.00	4150.00
Chana-Akola (N)	X	3937.50	3912.50
Coriander-Gondal (N)	X	6320.00	6125.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6300.00	6190.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6435.25	6298.00
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1874.60	1831.20
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1928.70	1893.65
Cotton-Kadi (N)	1 B	18979.20	18907.50
CPO-Kandla (M)	10 K	770.80	759.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	741.55	732.60
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	740.00	740.00
Gold Ahm (M)	10 G	40556.00	40589.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32575.00	32602.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4063.00	4074.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7066.65	6876.80
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3950.00	3850.00
Guarseed-Jodhpur (I)*	1 Q	3863.00	3892.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1093.25	1099.05
Isabgulseed-Unjha (I)*	1 K	103.15	103.40
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15000.00	14900.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14474.00	14411.10
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	840.00	830.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1023.25	1015.60
Kapas-Rajkot (N)	X	1018.50	1006.25
Lead Mum (M)	1 K	151.10	152.40
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1878.75	1820.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2115.90	2100.00
Maize-Erode (N)	X	1790.00	1805.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2115.90	2100.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2010.00	2000.00
Maize-Sangli (N)	X	1867.75	1857.90
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4631.25	4600.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7611.10	7562.50
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4231.00	4231.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	968.80	970.70
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3125.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)*	1 Q	3176.00	3160.00
Pepper-Ernakulam (I)*	1 K	327.80	328.20
Pepper-Kochi (N)	1 Q	32855.55	33122.20
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	830.00	820.00
Rape mustards-Patan (I)*	20 K	775.00	773.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1891.25	1880.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5365.65	5305.15
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	829.40	822.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	869.20	859.70
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	864.00	860.00
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	865.00	855.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13400.00	13575.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)*	1 Q	13350.00	13375.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46205.00	46205.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4189.00	4089.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4082.75	4020.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4267.25	4191.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4200.00	4100.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33000.00	32500.00
Soyoil-Indore (I)*	10 K	871.60	870.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3270.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3366.80	3380.95
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3285.50	3285.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3476.20	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3278.50	3275.25
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3150.00	3151.65
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5908.35	5900.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2210.60	2202.50
Wheat Kota (N)	1 Q	2176.65	2177.80
Wheat New Indore (N)	1 Q	2180.00	2175.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2105.00	2090.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2195.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5575.00	5650.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	175.40	172.30

* as on Feb 07, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (सोमवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19050, 19060, 18960, 19020	3138	398	27751
Mar 31	19280, 19310, 19240, 19290	1556	149	8219
Apr 30	19530, 19580, 19490, 19540	285	43	1412
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1793, 1814, 1746, 1754	13690	1037	29980
Mar 20	1810, 1815, 1762, 1772	47290	3249	73410
Apr 20	1831, 1831, 1787, 1797	5860	500	19930
May 20	1848, 1848, 1810, 1819	1300	116	5330
Jun 19	1856, 1868, 1856, 1859	210	18	210
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1054.5, 1054.5, 1047, 1051.5	224	43	920
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1058, 1059, 1047, 1052.5	963	497	3616
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1695, 1695, 1695, 1695	10	1	2430
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3914, 3928, 3806, 3816	21875	2006	18450
Mar 20	3956, 3968, 3846, 3854	45755	4708	68895
Apr 20	3976, 3976, 3884, 3892	1660	172	3400
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3852, 3894, 3830, 3844	4545	420	6740
Mar 20	3874, 3912, 3842, 3882	6740	768	21760
Apr 20	3902, 3920, 3860, 3906	1195	165	5550
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	752, 754.9, 736.6, 740.1	15470	1131	45290
Mar 31	747.4, 748.5, 731.7, 734.8	5470	368	21660
Apr 30	746.4, 747, 730.7, 732.8	730	49	6570
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1189, 1192, 1176.5, 1190.4	119.88	289	164.88
Mar 31	1175, 1182, 1175, 1180.6	18.72	45	69.84
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3993, 4014, 3952, 3974	4260	338	6690
Apr 20	4058, 4065, 3992, 4021	15650	1249	16670
May 20	4090, 4090, 4030, 4048	890	72	3910
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	850, 852.4, 840, 844.6	8765	1074	22025
Mar 20	839, 841, 827.2, 830.2	14015	1900	54035
Apr 20	836, 836, 822, 824	3420	471	6170
May 20	825, 825, 820, 820	25	4	105
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4052, 4056, 3932, 3942	27150	2353	42650
Mar 20	4060, 4064, 3912, 3926	57000	6178	146805
Apr 20	4062, 4062, 3910, 3922	18490	2428	92445
May 20	4082, 4082, 3936, 3944	1890	311	17010
Jun 19	4022, 4022, 3964, 3998	120	15	345
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	6920, 6938, 6671, 6694	7265	769	5110
Mar 20	7020, 7025, 6752, 6770	18710	2481	55230
Apr 20	7109, 7109, 6842, 6853	1550	180	3430
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3865, 3959, 3847, 3938	14390	1120	21290
Apr 20	3870, 3952, 3850, 3938	6230	539	17330
May 20	3903, 3994, 3898, 3969	1070	104	4760
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3620, 3650, 3520.2, 3589.1	3.9	25	3.1
Mar 13	3700, 3767, 3551, 3697.5	2.2	22	6.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6309, 6320, 6136, 6167	2000	189	7630
May 20	6240, 6240, 6160, 6160	90	9	770
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13655, 13730, 13500, 13510	441	138	2133
Apr 20	13505, 13720, 13425, 13450	354	106	1782
May 20	13525, 13525, 13525, 13525	9	3	9
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5880, 5916, 5842, 5884	960	155	4520
Apr 20	5852, 5910, 5852, 5898	615	89	4550
May 20	5882, 5920, 5882, 5920	20	4	140
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	138, 138, 136.3, 136.4	4384	3224	5391
Mar 31	138.3, 138.3, 137.15, 137.3	204	185	494
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	432.9, 433, 430.05, 430.4	15560	5011	12172.5
Mar 31	433.5, 434.15, 432.15, 432.35	177.5	70	1270
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	144.6, 144.8, 143.4, 143.55	4666	3300	6456
Mar 31	145.6, 145.7, 144.35, 144.5	231	183	682
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	949.5, 951.4, 942.6, 943.6	10726.5	6458	3505.5
Mar 31	949, 952.5, 945.7, 946.3	231	151	324
Zinc MCX(1 K)				
May 29	172, 172, 172, 172	2	2	15
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	170.5, 170.85, 167.4, 167.65	30507	16125	21886
Mar 31	171.95, 172, 168.6, 168.9	1042	830	4070
Apr 30	173, 173, 170, 171.85	3	3	10
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40566, 40710, 40514, 40615	4.83	4196	17.14
Jun 05	40730, 40868, 40708, 40781	0.13	94	5.72
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32270, 32372, 32270, 32346	0	171	0.01
Mar 31	32287, 32374, 32287, 32318	0	13	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40533, 40625, 40451, 40549	0.7	5747	0.85
Apr 03	40540, 40696, 40495, 40591	0.14	1173	0.33
May 05	40650, 40741, 40601, 40678	0	12	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4015, 4021, 4002, 4018	0	884	0.01
Mar 31	4036, 4040, 4025, 4035	0	266	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46097, 46319, 46000, 46248	206.22	5831	265.29
May 05	46605, 46817, 46540, 46768	2.91	94	29.16
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46091, 46330, 46021, 46261	23.69	17206	26.86
Apr 30	46667, 46834, 46561, 46780	1.63	1302	6.5
Jun 30	47281, 47300, 47099, 47273	0.01	7	0.17
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46117, 46325, 46011, 46261	67.76	10750	48.58
Apr 30	46630, 46860, 46570, 46779	1.83	339	7.84
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	133.1, 133.1, 127.7, 128.1	54954mb	23915	58125mb
Mar 26	135.8, 135.8, 131.5, 131.8	3241mb	1873	6591mb
Apr 27	138.4, 138.4, 136.7, 136.9	349mb	203	459mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3615, 3615, 3566, 3579	13423bl	79091	4302bl
Mar 19	3627, 3635, 3598, 3611	390bl	3284	455bl
Apr 20	3655, 3655, 3625, 3650	1bl	9	5bl
सायं सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19290, 19340, 19010, 19030	6182	952	28223
Mar 31	19530, 19610, 19290, 19310	2543	383	7530
Apr 30	19810, 19810, 19580, 19640	298	25	1263
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1072, 1075, 1055.5, 1059.5	296	69	896
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1072, 1074.5, 1056, 1059	1323	716	3447
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	751.5, 761.1, 747, 752	23870	1879	44050
Mar 31	744.5, 754.8, 741, 745.4	11900	857	20960
Apr 30	747.8, 754.8, 738.8, 743.5	1380	110	6570
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	850, 855.6, 845.2, 849.4	13635	1533	24755
Mar 20	836, 844.4, 833.2, 838.4	23055	2694	54655
Apr 20	831.8, 840.8, 830.4, 832.4	2280	334	5605
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	139, 139.2, 136.6, 137.85	13855	8550	4605
Mar 31	139.25, 139.3, 137.35, 138.45	510	406	412
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	433.5, 434.95, 430.35, 430.9	33775	11314	10727.5
Mar 31	436.35, 436.5, 432.2, 433	555	219	1250
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	146.15, 146.2, 144.5, 144.65	13808	8960	5607
Mar 31	146.8, 146.8, 145.4, 145.5	307	281	637
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	959.9, 962.2, 937, 940.7	27090	16458	2485.5
Mar 31	958.1, 960.2, 939.5, 942.6	588	313	259.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	172.65, 172.65, 169.55, 169.85	48426	27945	18711
Mar 31	173.45, 173.45, 170.8, 171.05	3523	2140	3803
Apr 30	173.2, 173.2, 172.25, 172.55	4	3	8
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40393, 40724, 40302, 40644	13.03	11284	16.9
Jun 05	40582, 40875, 40446, 40790	0.63	469	5.67
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32269, 32375, 32205, 32338	0.01	648	0.01
Mar 31	32217, 32370, 32204, 32343	0	108	0
Apr 30	32289, 32350, 31346, 32130	0	12	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40345, 40633, 40232, 40563	2	16772	0.75
Apr 03	40411, 40680, 40280, 40613	0.32	2736	0.32
May 05	40469, 40733, 40395, 40683	0.01	61	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	3996, 4024, 3996, 4019	0.01	2388	0.01
Mar 31	4021, 4040, 4020, 4036	0	567	0
Apr 30	4020, 4040, 4020, 4031	0	18	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46200, 46395, 45870, 46106	645.69	17874	244.29
May 05	46709, 46889, 46484, 46617	11.97	368	28.11
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46250, 46400, 45950, 46118	83.47	60982	24.07
Apr 30	46610, 46911, 46515, 46668	6.98	4967	6.47
Jun 30	47080, 47303, 47040, 47220	0.01	13	0.17
Aug 31	47013, 47300, 47013, 47157	0	2	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46200, 46417, 45930, 46117	229.57	36668	38.74
Apr 30	46769, 46915, 46500, 46663	7.26	1334	7.61
Jun 30	47200, 47200, 47200, 47200	0.01	1	0.05
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	134.6, 136.3, 132, 134.2	182474mb	83021	42963mb
Mar 26	136.6, 138.2, 134.7, 137.2	7655mb	4606	5943mb
Apr 27	140.7, 142, 139.2, 141.4	578mb	342	301mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3650, 3673, 3588, 3617	46279bl	266334	2652bl
Mar 19	3684, 3697, 3621, 3648	1284bl	10772	381bl
Apr 20	3652, 3830, 3652, 3678	2bl	11	4bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

एयर इंडिया को लाभ की उम्मीद!

अधिकांश यात्री चीन से होकर अमेरिका-कनाडा जाने वाली उड़ानों की बुकिंग करा रहे हैं रद्द

अनीश फडणीस

कोरोनावायरस के चलते चीन तथा हॉन्गकॉन्ग से होकर कनाडा एवं अमेरिका जाने वाली एयर इंडिया की नॉन-स्टॉप उड़ानों को फायदा होगा। सितंबर 2019 तक पिछले 12 महीनों में करीब 54 लाख यात्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच हवाई यात्रा की है। इनमें से करीब 25 प्रतिशत यात्रियों ने कहीं भी न रुकने वाली उड़ानें लीं और शेष उड़ानें दुबई, दोहा तथा फ्रैंकफर्ट जैसे स्थानों पर रुककर आगे जाती हैं।

इस अवधि में भारत-अमेरिका उड़ानों में से 5.7 प्रतिशत तथा दिल्ली से अमेरिका की ओर जाने वाली कुल 8 प्रतिशत उड़ानें चीन अथवा हॉन्गकॉन्ग में रुककर गई हैं। पंजाब से कनाडा जाने वाले यात्री कम किराया होने के कारण चीन तथा हॉन्गकॉन्ग में ठहरते/उड़ान बदलते हुए यात्रा करते हैं। ट्रैवल एजेंट तथा विमानन क्षेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तथा चीन के बीच उड़ानों के निलंबन से एयर इंडिया तथा दूसरी विमानन कंपनियों को विमानों में सीट भरने तथा बाजार हिस्सेदारी के रूप में मदद मिलेगी। एयर इंडिया प्रत्येक सप्ताह अमेरिका तथा कनाडा के लिए 36 उड़ानें भरती है और अपने कुल राजस्व का 12 फीसदी उत्तरी अमेरिकी रास्ते के जरिये कमाती है।

भारत में सबसे बड़ी यात्रा कंपनियों में से एक अकबर ग्रुप के मुख्य परिचालन अधिकारी अमेय अम्लादी कहते हैं, 'हम देख रहे हैं कि हवाई यातायात प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से अटलांटिक क्षेत्र की ओर जा रहा है। पूर्वी एशिया से होते हुए अमेरिका तथा कनाडा जाने वाली करीब 10 प्रतिशत बुकिंग रद्द करा दी गई हैं। इससे सबसे अधिक लाभ एयर इंडिया को होगा और इसके बाद प्रतिस्पर्धी किराए वाली यूरोपीयन विमानन कंपनियों को लाभ होगा।'

चंडीगढ़ स्थित प्रॉम्प्ट ट्रेवल्स के प्रबंधक अमित मिंगलानी कहते हैं, 'कोरोनावायरस से पहले चीन से होते हुए टोरंटो तथा वेंकूवर जाने वाली हवाई यात्राएं काफी लोकप्रिय थीं, क्योंकि ये बाकी उड़ानों से 15-20 प्रतिशत सस्ती थीं। लेकिन अब ग्राहक चीनी विमानन कंपनियों में यात्रा करने से बच रहे हैं और अपनी यात्राएं एयर कनाडा या दूसरी विमानन कंपनियों में बुक करा रहे हैं।' चार चीनी विमानन कंपनियां दिल्ली के लिए हवाई यात्राएं कराती हैं और वायरस के फैलने के बाद वे अपनी उड़ानों में कटौती कर रहे हैं। एयर चाइना और शेडोंग एयरलाइन ने अपनी भारतीय उड़ानों को स्थगित कर दिया है जबकि चाइना साउथर्न एयरलाइन तथा चाइना इस्टर्न एयरलाइन ने दिल्ली की यात्राओं में कटौती की है।

हॉन्गकॉन्ग स्थित कैथे पैसिफिक भारत के छह शहरों के लिए सप्ताह में 49 उड़ानें चलाती थी लेकिन अब कंपनी ने कम मांग के चलते फरवरी तथा मार्च के लिए इनकी संख्या घटाकर 36 कर दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'हम कनाडा तथा अमेरिका तक यात्रियों को ले जाते हैं। हम बुकिंग के साथ साथ टिकट रद्द कराने के मामले भी देख रहे हैं। इसलिए, फिलाहल इसके वास्तविक प्रभाव के बारे में नहीं बता सकते।'

एविएशन ब्लॉग 'नेटवर्क थॉट्स' के संस्थापक अमेया जोशी कहते हैं, 'अगर प्रशांत क्षेत्र से तथा चीनी विमानन कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली उड़ानें रद्द की जाती हैं तो एयर इंडिया गर्मियों में कुछ और नई उड़ानें शुरू कर सकती है। सप्ताह में भारत के लिए यूनाइटेड की 21 तथा डेल्टा की 7 उड़ानें हैं और गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में एयर इंडिया मजबूत कंपनी है। जिस तरह सिंगापुर में कोरोनावायरस को लेकर चिंता बढ़ रही है, लोग सिंगापुर से जाने वाली उड़ानें लेने से बच रहे हैं और यूरोप तथा मध्य पूर्व से होते हुए जाने के विकल्प को चुन रहे हैं।' ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ज्योति मयाल कहती हैं, 'यात्री दक्षिण-पूर्वी एशिया के रास्ते से परहेज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की उड़ानें भी रद्द हो रही हैं।'

सिंगापुर एयरलाइन ने एक बयान में कहा, 'हम नोवल कोरोनावायरस हमले के बाद की स्थिति पर गहन निगरानी रख रहे हैं। इससे कारोबार पर पड़े प्रभाव की पूरी गणना करना अभी जल्दी होगा।'

हवाई सफर का आंकड़ा

- दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए एयर इंडिया, यूनाइटेड तथा एमीरेट्स सबसे अधिक उड़ानों का परिचालन करती हैं
- दिल्ली के लिए चार चीनी विमानन कंपनियां देती हैं सेवाएं
- भारत-अमेरिका उड़ानों के लिए एमिरेट्स सबसे बड़ी हवाई कंपनी
- घटते यात्रियों के चलते चीनी विमानन कंपनियों ने सेवाएं रद्द या उड़ानों में कमी कर दी है
- दिल्ली से अमेरिका की ओर जाने वाली कुल 8 प्रतिशत उड़ानें जाती हैं चीन अथवा हॉन्गकॉन्ग में रुककर
- पंजाब के अधिकांश चीन के रास्ते जाते हैं कनाडा

वायरस असर: पहली तिमाही में वैश्विक वृद्धि दर कम

पुनीत वाधवा

चीन में कोरोनावायरस का कहर गंभीर होने से विश्व व्यापार पर इसका असर दिख रहा है। ऐसे में ज्यादातर विश्लेषकों ने कैलेंडर वर्ष 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमानों को कम करना शुरू कर दिया है जिसका आकलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से होता है। मिसाल के तौर पर यूबीएस में मौजूद विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बाद के दौर से वैश्विक वृद्धि के लिए सबसे कमजोर तिमाही साबित होगी और यह दौर 1990 के दशक के आखिर में बने एशियाई संकट के समान ही है।

यूबीएस में आर्थिक शोध के वैश्विक प्रमुख एरेंड कैपटीन के मुताबिक वैश्विक जीडीपी को बड़ा झटका लगेगा और वैश्विक वृद्धि दर दिसंबर 2019 की तिमाही के 3.2 फीसदी से घटकर जनवरी 2020 की तिमाही में 0.7 फीसदी के स्तर पर आ जाएगी। उनके मुताबिक अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में वैश्विक वृद्धि में सुधार आएगा लेकिन 2020 की कुल जीडीपी वृद्धि में 20 आधार अंक तक की कमी आएगी और यह 2.9 फीसदी के स्तर पर रह सकती है।

> वायरस के असर से वैश्विक जीडीपी जनवरी 2020 की तिमाही में घटकर 0.7 फीसदी पर होगी

यूबीएस के मुताबिक फिलहाल चीन से आने और चीन जाने वाले पर्यटकों की तादाद में कमी, चीन से आयात की मांग खासतौर पर उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आने और वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के मकसद से देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से आर्थिक गतिरोध की स्थिति बनी है। यूबीएस की रिपोर्ट में कहा गया, 'हम चीन में आयात वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं जो चौथी तिमाही के 3.2 फीसदी से घटकर पहली तिमाही में -4 फीसदी तक हो सकता है। दूसरी तिमाही में वृद्धि में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं हालांकि इसमें चीन के उपभोग स्तर में कमी भी परिलक्षित हो सकती है जबकि तीसरी तिमाही में सुधार से यह अंदाजा मिलेगा कि खासतौर पर चीन में प्रोत्साहन पैकेज का असर देर से दिखना शुरू हो गया है।'

कोरोनावायरस के संदिग्ध और पुष्ट मामलों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है और रिपोर्ट के मुताबिक चीन में मौजूद करीब 99 फीसदी इसकी चपेट में हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्स के मुकाबले इस बार कोरोनावायरस की महामारी का आर्थिक असर काफी व्यापक हो सकता है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया का योगदान ज्यादा है जो वर्ष 2003 के 21 फीसदी से बढ़कर अब 37 फीसदी तक हो चुका है।

भारत पर असर

चीन के संदर्भ में देखें तो जनवरी 2020 की तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान की तस्वीर ज्यादा चिंताजनक नजर आ रही है। नोमुरा के बाजार शोध के सह प्रमुख रॉब सुब्बारमन, और सोनल वर्मा तथा रेबेका वांग जैसे विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान चीन में जीडीपी वृद्धि कम होकर 3.8 फीसदी रह सकती है जो पिछली समान तिमाही में 6 फीसदी तक थी। हालांकि उन्हें यह भी उम्मीद है कि 2020 की दूसरी तिमाही में उत्पादन और मांग बढ़ने से यह 6.4 फीसदी तक हो सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट का कहना है, 'चीन की अर्थव्यवस्था का वैश्विक जीडीपी में करीब 16 फीसदी तक का अनुमान है जो 2003 में सार्स के दौरान 4 फीसदी तक था। हमारे नतीजे यह दर्शाते हैं कि एशिया के शीर्ष 10 में से 9 देशों मसलन हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और भारत असुरक्षित हैं।'

कोरोनावायरस पर नियंत्रण के बाद वृद्धि में सुधार की उम्मीद

हालांकि नोमुरा का यह भी अनुमान है कि चीन में कोरोनावायरस की संक्रमण दर फरवरी के आखिर में कम होना शुरू हो जाएगा जिससे सरकार मार्च में चीन के बड़े शहरों में बंदी में ढील दे सकती है। इसके साथ ही चीन के बाहर संक्रमण दर में बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि यूबीएस ने भी अनुमान लगाया है कि चीन की जीडीपी पहली तिमाही में 3.8 फीसदी के स्तर पर सिमट जाएगी हालांकि दूसरी तिमाही में इसमें वृद्धि दिखेगी।

यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'चीन की 2020 की 5.4 फीसदी जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को कम करते हैं। एक बार जब कोरोनावायरस पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा और गतिविधियां सामान्य होती हैं तब हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में जीडीपी वृद्धि 6 फीसदी के स्तर पर आ जाएगी। वायरस से उपभोग पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ा है लेकिन चीन का दीर्घावधि रुझान यह है कि यह उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है और कुल अर्थव्यवस्था में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही तकनीकी सुधार भी जारी रहना चाहिए।'

कच्चे तेल का कारोबार गिरा

वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के बीच हाजिर बाजार में सटोरियों के अपने सौदे घटाने से कच्चा तेल वायदा भाव सोमवार को 20 रुपये तक गिर गया। एमसीएक्स पर फरवरी डिलिवरी सौदों में कच्चा तेल वायदा भाव 20 रुपये यानी 0.55 प्रतिशत गिरकर 3,597 रुपये प्रति बैरल रहा। इसके लिए 30,080 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह मार्च डिलिवरी के लिए यह भाव 17 रुपये यानी 0.47 प्रतिशत टूटकर 3,631 रुपये प्रति बैरल रहा। इसके लिए 975 लॉट का कारोबार हुआ।

दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर ब्रेंट कच्चा तेल भाव 0.07 प्रतिशत बढ़कर 54.51 डॉलर प्रति बैरल रहा। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल भाव 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 50.37 डॉलर प्रति बैरल रहा। हालांकि, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के नरम पड़ने और अन्य प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की कमजोरी से रुपये को बल मिला। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 71.30 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

विदेशी विनिमय बाजार के डीलरों के अनुसार घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली का जोर न होता तो रुपया और मजबूत हो सकता था। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया-डॉलर विनिमय दर 71.36 रुपये पर खुली। दिन में स्थानीय मुद्रा की दर एक समय मजबूत होकर 71.28 रुपये प्रति डॉलर तक चली गयी थी। बाद में यह गिरकर 71.43 प्रति डॉलर पर भी आई। *एजेंसियां*

मास्क की मांग तेज कई गुना हुए दाम

रामवीर सिंह गुर्जर

कोरोनावायरस से देश में मास्क की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है क्योंकि इस संक्रमित वायरस से बचाव के लिए मास्क भी अहम उपाय है। मास्क की मांग इतनी बढ़ गई है कि बाजार में इसकी किल्लत है और इसके दाम दो से तीन गुना तक बढ़ चुके हैं। देश में चीन से बड़े पैमाने पर मास्क आयात किए जाते हैं, लेकिन चीन में कोरोनावायरस के कहर से अब चीन के कारोबारी भारत से मास्क के ऑर्डर दे रहे हैं।

दिल्ली के भागीरथ प्लेस में देश का अहम दवा बाजार है। इस बाजार के दवा और मास्क कारोबारी अमित कहते हैं कि चीन में कोरोनावायरस के कहर के कारण देश में भी लोग इस वायरस से डरे हुए हैं और इससे बचाव के लिए मास्क खरीद रहे हैं। इन दिनों अस्पतालों व डॉक्टरों को छोड़कर आम जनता की ओर से मास्क की मांग कमजोर ही रहती थी। लेकिन इस बार कोरोनावायरस के कारण मास्क की मांग अचानक बढ़ गई है।

आमतौर पर इन दिनों 1,000 से 1,500 मास्क ही बिकते थे। लेकिन अब 4,000-5,000 मास्क बिक रहे हैं। अभी एक 10 हजार मास्क का ऑर्डर रद्द करना पड़ा है क्योंकि बाजार में मास्क की किल्लत है। मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने के कारण 50-70 रुपये में मिलने वाले एन-95 मास्क की कीमत बढ़कर 120 से 140 रुपये हो गई है। साधारण मास्क की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 250 से 300 रुपये पैकेट हो गई है। इसी बाजार के मास्क कारोबारी अमन ने कहा कि चीन में मास्क का उत्पादन ठप है और कोरोना के कारण इसकी मांग काफी ज्यादा है। जिससे चीन के एक कारोबारी ने 7 लाख मास्क का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही देश में भी बड़े पैमाने पर मास्क के ऑर्डर मिल रहे हैं। बाजार में मास्क की किल्लत को देखते हुए पूरे ऑर्डर की पूर्ति कर पाना मुश्किल लग रहा है। मास्क के ऑर्डर के लिए अग्रिम भुगतान की मांग की जा रही है। कोरोनावायरस के कारण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी 4 लाख से अधिक मास्क वितरित किए जा रहे हैं।

देश में भी मास्क की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है